सब का सपना

निष्पक्ष व निडर - हिंदी दैनिक समाचार पत्र

शुक्राना यात्रा का आखिरी दिन, बठिंडा पहुंचे सीएम मान.... पेज: 7

पवन सिंह से ब्रेकअप के बाद फिर इश्क में पड़ीं अक्षरा सिंह पेज: 8

वर्ष : 02 | अंक : 38 | शनिवार 09 मई 2026 | अमरोहा (उत्तर प्रदेश) | www.sabkasapna.com | पृष्ठ : 08 | मूल्य: 2 रुपए

स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार ने कहा, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा जिम्मेदारी

पटना (एजेंसी)। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार ने शुक्रवार को बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। पद संभालने के बाद उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में निशांत कुमार ने कहा, 'मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करूंगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम करूंगा।' इस अवसर पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने भी निशांत कुमार के राजनीति में आने और मंत्री बनने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बेटे को 21 वर्षों तक राजनीति से दूर रखा, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की जरूरत को देखते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने विश्वास जताया कि निशांत कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में बेहतर काम होगा। बिहार सरकार में गुरुवार को हुए बड़े मंत्रिमंडल विस्तार में 32 मंत्रियों को शामिल किया गया था। यह विस्तार एनडीए सरकार बनने के बाद प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया।

ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ केमिस्टों की हड़ताल, 20 मई को महाराष्ट्र समेत देशभर में मेडिकल स्टोर रहेंगे बंद

मुंबई (एजेंसी)। आगामी 20 मई को महाराष्ट्र समेत देशभर में मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। दरअसल अखिल भारतीय औषध विक्रेता संगठनों द्वारा ऑनलाइन दवाओं की कथित अवैध बिक्री और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के बढ़ते दबदबे के विरोध में राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल का असर राज्य के सभी शहरों और ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलेगा। संगठनों का कहना है कि बिना उचित जांच-पड़ताल और नियमों के इंटरनेट के माध्यम से दवाओं की बिक्री की जा रही है, जिससे न केवल छोटे मेडिकल दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है बल्कि मरीजों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संगठन के अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे ने कहा कि प्रशासन की अनदेखी के कारण मजबूर होकर दवा विक्रेताओं को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियम लागू करने और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा की मांग को लेकर यह बंद किया जा रहा है। हालांकि, हड़ताल के दौरान गंभीर मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए जीवनरक्षक और अत्यावश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। संगठन ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरत की दवाएं पहले से खरीदकर रखें ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

राहुल गांधी आय से अधिक संपत्ति मामला-हाई कोर्ट ने बंद कमरे में सीलबंद कराई केस फाइल

लखनऊ (एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में अहम सुनवाई की। मामले की संवेदनशीलता और दस्तावेजों की प्रकृति को देखते हुए अदालत ने न केवल सुनवाई 12 मई तक टाल दी, बल्कि पूरी केस फाइल को सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का आदेश भी दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई के दौरान ही सीलबंद फाइल खोली जाएगी। इस मामले को लेकर अदालत ने प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरतते हुए इसे इन-चैंबर (बंद कमरे) में सुना, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस जफीर अहमद की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी एजेंसियों के अधिवक्ताओं ने अदालत से कहा कि उन्हें संबंधित विभागों से लिखित निर्देश प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इस पर अदालत ने सहमति जताते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 मई निर्धारित कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि तब तक सभी संबंधित पक्ष आवश्यक निर्देश प्राप्त कर लें। विदित हो कि यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अज्ञात स्रोतों से बड़ी संपत्ति अर्जित की है, जिसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। याचिका में केंद्र सरकार के साथ-साथ सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने इन सभी एजेंसियों से व्यापक जांच कराने की मांग की है। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर इससे पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में याचिका दाखिल कर चुके हैं। मौजूदा याचिका में उन्होंने आय से अधिक संपत्ति का मुद्दा उठाते हुए विस्तृत जांच की मांग की है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी। उसी दिन सीलबंद फाइल अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट पर ईडी का बड़ा एक्शन, तीन संस्थापक गिरफ्तार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेक्टर से जुड़ी बड़ी कंपनी गेम्जक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा एक्शन लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग और कथित धोखाधड़ी के मामले में कंपनी के तीन संस्थापकों दीपक सिंह, पृथ्वीराज सिंह और विकास तनेजा को गिरफ्तार किया गया है। ईडी की यह कार्रवाई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से जुड़े कई गंभीर आरोपों के बाद सामने आई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक, गेम्सक्राफ्ट और उससे जुड़ी अन्य संस्थाओं के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में कई एफआईआर दर्ज थीं। इन शिकायतों में लोगों को गुमराह करने, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए आर्थिक नुकसान पहुंचाने और अवैध तरीके से धन जुटाने जैसे आरोप लगाए गए हैं।

बोहरा समुदाय में छोटी बच्चियों की खतना पर सुपीम कोर्ट में बहस, जस्टिस हैरान

-महिला ने कहा- इस प्रथा को पॉक्सो ऐक्ट के तहत अपराध घोषित किया जाए

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुस्लिमों के दाऊदी बोहरा समुदाय में छोटी बच्चियों का खतना किए जाने की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को बहस हुई। इस प्रथा पर सवाल उठाते हुए एक दाऊदी बोहरा महिला ने कहा कि इसके तहत बच्चियों के जननांग के एक हिस्से को काटा जाता है। इस दौरान उन्हें बेहद पीड़ा से गुजरना होता है। यह ट्रॉमा ऐसा होता है कि उन्हें पूरी जिंदगी इससे होने वाली शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरना होता है। उन्होंने कहा कि इस खतना के दौरान हजारों नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। महिला ने कहा कि इससे स्वास्थ्य को खतरा होता है और उनकी गरिमा से भी समझौता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने कहा कि इस प्रथा को तो पॉक्सो ऐक्ट के तहत अपराध घोषित किया जाना चाहिए। दाऊदी बोरा समुदाय की महिला की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि खतना की यह प्रथा 7 साल की बच्चियों के साथ होती है। उन्होंने कहा कि जब 7 साल की बच्ची के साथ इसे अंजाम दिया जाता है तो फिर सहमति का तो सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि बच्ची की सहमति की बात नहीं हो सकती और उसके परिजन सामाजिक दबाव में रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वे विरोध करेंगे तो उनके सामाजिक बहिष्कार का खतरा रहता है।

वकील ने कहा कि परिजन चुप रहते हैं क्योंकि यदि उनका बहिष्कार हुआ तो फिर वे ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जहां उनको समाज से बॉयकॉट कर दिया जाता है। समाज के साथ उनके आर्थिक और सामाजिक रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इस विषय को भले ही सामाजिक प्रथा कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से एक बच्ची को पीड़ा झेलनी पड़ती है वह मामला संवैधानिक और आपराधिक दायरे में चला जाता है। ऐसे में इस पर उसी आलोक में विचार किया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार समेत 9 जज शामिल हैं। इस मामले की सुनवाई में जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने हैरानी भी जताई कि आखिर इसके खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं बना है। ऐसे में कोई कानून जरूर बनना चाहिए, जिससे इस पर रोक लग सके। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में कानून बनाकर रोक लगाने का अधिकार तो सरकार के पास ही है।

फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के सामने चोर, चोर टीएमसी चोर और जय श्री राम जैसे नारे लगे

कोलकाता(एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की करारी हार के बाद राज्य की राजनीतिक तपिश अब विमानों के भीतर भी महसूस हो रही है। कृष्णानगर से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि इंडिगो की एक फ्लाइट में उनके साथ बदसलूकी की गई। कृष्णानगर से लोकसभा सांसद मोइत्रा ने एक्स पर कुछ वीडियो शेयर किए, जिसमें कुछ लोगों को चोर, चोर टीएमसी चोर, तृणमूल ईर शोब चोर और जय श्री राम जैसे नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। टीएमसी की मोइत्रा ने इस नारेबाजी को नागरिकों का गुस्सा नहीं बताया और एक परेशानी कहा, जिसने विमान में उनकी सुरक्षा का उल्लंघन किया। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के खिलाफ अपने सख्त रुख के लिए मशहूर महुआ ने इंडिगो से इन लोगों के नाम सार्वजनिक करने और उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डालने को कहा, साथ ही उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को भी इस बारे में टैग किया। मोइत्रा ने पोस्ट में कहा यह बीजेपी की संस्कृति है। किसी को हैरानी क्यों हो रही है? मैंने इस नज़रअंदाज़ किया और हवाई अड्डे से अपनी बैठक में चली गई। फिर लोगों ने मुझे वह वीडियो भेजा जिसे संघी लोग वायरल कर रहे थे। तभी मैंने इस पर आवाज उठा दी। टीएमसी नेता ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) में औपचारिक शिकायत दर्ज की है, जिसमें उन्होंने कहा कि चार-पांच युवकों ने इसतहर के नारे लगाए जो सीधे तौर पर उन्हें और उनकी पार्टी को निशाना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि उन पर मौखिक हमला हुआ और उन्हें परेशान किया गया, और साथ ही यह भी जोड़ा कि उनके पास इस मौखिक दुर्व्यवहार से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने दावा किया कि इंडिगो के किसी भी अधिकारी ने बीच-बचाव नहीं किया, और उन्होंने एयरलाइन के कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की। इंडिगो ने अभी तक उनके आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा ये नारे और उद्घोष मेरी पार्टी (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस), मेरी पार्टी के नेताओं और मुझ पर व्यक्तिगत रूप से निशाना साध रहे थे। एक बंद विमान के अंदर मुझ पर मौखिक हमला कर मुझे परेशान किया गया, और चूंकि मुझे विमान से उतरने की प्रक्रिया शुरू होने तक इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए मेरे पास इस मौखिक दुर्व्यवहार से बचने का कोई रास्ता नहीं थाजो सीधे तौर पर मुझ पर किया जा रहा था।

तमिलनाडु में राज्यपाल की भूमिका पर चिदंबरम ने उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली में तमिलनाडु की नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब राज्यपाल का कर्तव्य होता है कि वह सदन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा कि यह केवल राजनीतिक परंपरा ही नहीं, बल्कि संसदीय व्यवस्था का स्थापित नियम भी है। उन्होंने लिखा कि निर्वाचित विधायकों की संख्या के आधार पर सबसे बड़े दल के नेता को पहले सरकार गठन का मौका मिलना चाहिए। इसके बाद वह विधानसभा में बहुमत साबित कर सकता है। कांग्रेस नेता ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट के 1994 के ऐतिहासिक फैसले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधानसभा को ही बहुमत परीक्षण का सही मंच माना है। चिदंबरम ने उन तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों की भी सराहना की, जिन्होंने इस सिद्धांत को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया और उसका समर्थन किया।

दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इस बार किसी भी दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ है। अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे अभी भी करीब 10 विधायकों के समर्थन की जरूरत है।

बहुमत का आंकड़ा नहीं होने की वजह से राज्यपाल ने अभी तक विजय को सरकार गठन का न्योता नहीं दिया है। हालांकि, कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान किया है। इसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां और तेज हो गई हैं।

अखिलेश को झटका, सपा के कई दिग्गज नेता सुभासपा में शामिल

लखनऊ (एजेंसी)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपना कुनबा बढ़ाने और संगठन विस्तार के अभियान को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को पार्टी को उस वक्त बड़ी मजबूती मिली, जब समाजवादी पार्टी और बुनकर मजदूर विकास समिति से जुड़े लगभग 30 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, ग्राम प्रधानों और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सुभासपा का दामन थाम लिया। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर की उपस्थिति में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में इन सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

पार्टी में शामिल होने वाले प्रमुख चेहरों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आलम का नाम सबसे ऊपर है, जिनका सुभासपा में आना विपक्षी खेमे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके साथ ही बुनकर मजदूर विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद नाजिम अंसारी और युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताजुद्दीन अंसारी ने भी पार्टी की विचारधारा पर भरोसा जताया। सदस्यता लेने वाले अन्य नेताओं में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष खालिद सैफी, राष्ट्रीय सचिव अयूब अंसारी, प्रदेश प्रभारी कारी लाइक अंसारी और कई जिला अध्यक्ष शामिल हैं। ये नेता दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, शाहदरा, प्रतापगढ़, अमरोहा और लखनऊ जैसे विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे सुभासपा का प्रभाव कई जिलों में बढ़ने की उम्मीद है।

इस अवसर पर अरुण राजभर ने विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे पर तंज कसते हुए इसे केवल राजनीतिक स्वार्थ का जरिया बताया। राजभर ने कहा कि सपा का यह नारा जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि उनकी अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से बदलता रहता है। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनके लिए पीडीए का असली अर्थ पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश है, जो केवल परिवारवाद तक सीमित है। राजभर ने दावा किया कि जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के नेता सुभासपा से जुड़ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि जनता और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अब बदलाव चाहते हैं। संगठन में हुए इस बड़े विस्तार से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और इसे आगामी चुनावी जंग के लिए सुभासपा की एक बड़ी रणनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है।

अपहरण के मामलों ने बढ़ाई चिंता, देश में 10 साल में 10 लाख मामले सामने आए

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित सिविल सेवा परीक्षा कोचिंग सेंटर की निदेशक शुभ्रा रंजन का 3 मई को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया था और 1.89 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिरौती मांगी गई थी। इस तरह के अपराध का यह अकेला मामला नहीं है। पिछले एक दशक में 10 लाख से ज्यादा अपहरण के मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक यही नहीं, वर्ष 1953 से 2024 के बीच अपहरण और अगवा करने के 20 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जो भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज कुल मामलों का करीब 1.7 फीसदी है। कुल मामलों में से 54 फीसदी 2013 से 2024 के बीच सामने आए हैं। इस अवधि में केवल 0.7 फीसदी मामले ही फिरौती से जुड़े हैं। वर्ष 1953-62 के दशक के बाद से अपहरण के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। आईपीसी मामलों में इनकी हिस्सेदारी 1973-82 के दशक से बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक अपहरण के मामलों में फिरौती बड़ी वजह नहीं रही है। सबसे अधिक मामले लोगों को जबरन उठाने यानी अपहरण से जुड़े हैं, जो कुल मामलों के आधे से भी ज्यादा हैं। इसके बाद शादी के लिए महिलाओं के अपहरण के मामले आते हैं, जबकि फिरौती के लिए अपहरण या अगवा करने के मामलों की हिस्सेदारी इनमें बहुत कम है। अपहरण के मामलों में शीर्ष छह राज्यों में से बिहार 2024 में सबसे नीचे रहा। पिछले कुछ सालों में यह राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर रहा है।

राघव चड्ढा की देशवासियों से अपील, एकजुट रहे... भारत आतंकवाद, क्रूरता और बर्बर मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली में शुक्रवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर कड़ा बयान दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपने वीडियो संदेश में उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की और भारतीय सेना के साहस तथा पराक्रम की जमकर सराहना की।

'जय हिंद साथियों' से अपने संदेश की शुरुआत कर बीजेपी नेता चड्ढा ने कहा कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, लेकिन अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो, तब सही रास्ते पर लाने के लिए कठोर कदम उठाना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बल्कि आतंकवाद, क्रूरता और बर्बर मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है।

बीजेपी नेता चड्ढा ने कहा कि सेना इस बार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं

और आतंक की जड़ों को खत्म करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों और उनके परिवारों के प्रति समर्थन जताकर कहा कि पूरे देश को उनके साथ ÷चट्टान की तरह÷ खड़ा रहना चाहिए।

उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र कर कहा कि निहत्थे नागरिकों की हत्या मानवता पर एक बड़ा कलंक है। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। चड्ढा ने दावा किया कि भारत ने इसका जवाब 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए देना शुरू कर दिया है और भारतीय वायुसेना तथा मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को प्रभावी ढंग से नष्ट कर रहा है।

अपने बयान में उन्होंने देश में हुए कई बड़े आतंकी हमलों का उल्लेख किया, जिनमें 2008 मुंबई आंतकी, पुलवामा अटैक, उरी अटैक, भारतीय संसद हमला और 1993 बॉम्बे बम विस्फोट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना इन हमलों के जिम्मेदार आतंकियों और उनकी सोच को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है।

शशि थरूर अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

-कोर्ट से अपील- डीपफेक वीडियो और एआई-मॉर्फ्ड कंटेंट को तुरंत हटाए जाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। थरूर ने आरोप लगाया है कि उनकी सहमति के बिना उनके नाम, छवि और व्यक्तित्व का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की पीठ करेगी।

कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में कई आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से राहत मांगी है। इसमें कई अज्ञात लोग भी शामिल हैं। थरूर ने कोर्ट से अपील की है कि इंटरनेट और अन्य प्लेटफॉर्म से कई डीपफेक वीडियो और एआई-मॉर्फ्ड कंटेंट को तुरंत हटाया जाए। बता दें थरूर की ओर से यह याचिका लॉ फर्म ट्राईलीगल के पार्टनर और वकील निखिल नरेंद्रन के जरिए दायर की गई है। थरूर अब उन अभिनेताओं, क्रिकेटरों और अन्य मशहूर हस्तियों की लंबी सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने पब्लिक और पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर भी कोर्ट से इसी तरह का इंजंक्शन हासिल कर चुके हैं। कोर्ट ने विज्ञापनों, मर्चेंडाइज और एआई-जनरेटेड कंटेंट में इन सितारों के नाम, आवाज, तस्वीर और हुबहू पहचान के बिना इजाजत इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाई थी। अब शशि थरूर ने भी अपने अधिकारों को महफूज रखने और अपने नाम-पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यही कानूनी रास्ता अपनाया है। केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर पूर्व राजनयिक और प्रसिद्ध लेखक भी हैं। राजनीति में कदम रखने से पहले, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में करीब तीन दशकों तक अपनी सेवाएं दीं और अंडर-सेक्रेटरी-जनरल के प्रतिष्ठित पद तक पहुंचे। भारत सरकार में वे विदेश मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार भी संभाल चुके हैं।

बंगाल में राइटर्स बिल्डिंग से चलेगी नई सरकार! 1777 में बनी थी यह इमारत

-इस पर अंतिम फैसला नए सीएम ही लेंगे, नबान्न नहीं होगा ठिकाना

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सरकार के कामकाज का केंद्र भी बदलने वाला है। निवर्तमान सीएम ममता बनर्जी के 15 साल के कार्यकाल में 13 साल तक सत्ता का केंद्र रहा नबान्न अब नई सरकार का ठिकाना नहीं होगा। राज्य में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी राज्य सचिवालय को हावड़ा से वापस कोलकाता स्थित ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग में शिफ्ट करने की योजना बना रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने नबान्न में कार्यवाहक मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला से मुलाकात की। समिक ने उन्हें सूचित किया है कि नए सीएम के शपथ लेने के बाद सचिवालय को शिफ्ट कर दिया जाएगा। बीजेपी के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के शनिवार सुबह ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेने की उम्मीद है। इसके बाद नए नेता मध्य कोलकाता स्थित राइटर्स बिल्डिंग से अपना कार्यभार संभालेंगे। हालांकि, बीजेपी ने अभी तक अपने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी हमेशा से इसके ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए सचिवालय को वापस राइटर्स बिल्डिंग में ले जाने की इच्छुक रही है। इस कदम का समर्थन करते हुए समिक भट्टाचार्य ने कहा कि हम 2021 से ही कह रहे हैं कि हम राइटर्स बिल्डिंग से सरकार चलाएंगे। मैंने इस साल चुनाव प्रचार के दौरान भी यह घोषणा की थी। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला नए सीएम ही लेंगे। 250 से ज्यादा सालों तक राइटर्स बिल्डिंग सत्ता का केंद्र रही है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश इंडिया और आजादी के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने अक्टूबर 2013 तक यहीं से कामकाज किया।

रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में पहली बार शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने भी राइटर्स बिल्डिंग से ही कार्यभार संभाला था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना सचिवालय अस्थायी तौर पर गंगा पार हावड़ा के शरत चटर्जी स्ट्रीट स्थित नबान्न में शिफ्ट कर लिया था। ममता सरकार ने तब पुरानी इमारत में आग और आपदा से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए इसके जीर्णोद्धार के लिए करीब 200 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ममता ने तब इसे बारूद का ढेर बताते हुए कहा था कि सुरक्षा के लिहाज से अस्थायी जगह तलाशी जा रही है। हालांकि, इमारत का काम पूरा न होने के कारण सरकार की वहां कभी वापसी नहीं हो सकी।

नवीनीकरण के तहत लोक निर्माण विभाग ने इमारत की मूल ई संरचना के बीच बने दो एनेक्सी भवनों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद काम धीमा पड़ गया। राइटर्स बिल्डिंग में मूल रूप से करीब 3 लाख वर्ग फुट का कार्यक्षेत्र था, जो तोड़े जाने के बाद घटकर 2.5 लाख वर्ग फुट रह गया। हालांकि यह जगह सीएमओ समेत कम से कम 8-10 विभागों के लिए पर्याप्त है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि अगर नई सरकार तुरंत वापस लौटना चाहती है, तो उसके लिए केवल ब्लॉक 1 और 2 ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं। नया सीएमओ दूसरी मंजिल पर काम कर सकता है, जहां जीर्णोद्धार का काम पूरा हो चुका है। मूलरूप से सीएमओ पहली मंजिल पर था, जिसकी मरम्मत में अभी 6 महीने और लग सकते हैं। इस बीच, कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद ने सुरक्षा व्यवस्था और नवीनीकरण कार्य का जायजा लेने के लिए बुधवार को राइटर्स बिल्डिंग का दौरा किया था।

बता दें वर्ष 1777 में बनी राइटर्स बिल्डिंग को थॉमस लियोन ने डिजाइन किया था। इसका निर्माण गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से तीन साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे खरीद लिया था, जिसके बाद यह क्लर्कों के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल होने लगी। 1906 के आसपास इस लाल रंग की शानदार इमारत को इसका खास ग्रीको-रोमन लुक मिला। डलहौजी स्क्वायर पर स्थित यह इमारत भारत और बंगाल के इतिहास की मूक गवाह रही है, लेकिन अब सरकार के यहां लौटने से पहले इसे एक गंभीर कायाकल्प की जरूरत है।

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन है वैचारिक बदलाव का संकेत

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। भाजपा की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल अब राजनीतिक रूप से 'अपवाद' नहीं रहा। यहाँ भी वही प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं जो देश के अन्य हिस्सों में प्रभावी हैं-सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सामाजिक संतुलन। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं।

पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों को केवल एक राजनीतिक दल की जीत या हार के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह परिणाम उस वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरे हैं, जो लंबे समय से बंगाल की राजनीति के भीतर सुलग रहा था। वर्षों तक बंगाल को एक ऐसे राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां कथित रूप से जाति, धर्म और पहचान की राजनीति नहीं चलती, बल्कि विचारधारा, वर्ग-संघर्ष और बंगालियत की राजनीति प्रभावी रहती है। किंतु 2026 के चुनाव परिणामों ने इस स्थापित धारणा को गहराई से चुनौती दी है। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान में आए परिवर्तन का भी संकेत है। मतदाता अब केवल भावनात्मक नारों या वैचारिक रोमांटिसिज्म के आधार पर मतदान नहीं कर रहा, बल्कि वह अपनी सांस्कृतिक पहचान, सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और भविष्य को भी ध्यान में रख रहा है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व सफलता को अनेक विश्लेषक एक प्रकार के 'सांस्कृतिक पुनर्जागरण' के रूप में देख रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में 'बंगाली अस्मिता' और 'हिंदू पहचान' के बीच एक वैचारिक द्वंद्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। तृणमूल कांग्रेस ने स्वयं को बंगाल की संस्कृति और क्षेत्रीय गौरव का संरक्षक बताया, जबकि भाजपा ने राष्ट्रीयता, हिंदुत्व और सांस्कृतिक चेतना को अपने राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया। वास्तव में बंगाल की ऐतिहासिक चेतना कभी संकुचित नहीं रही। यह वही भूमि है जहाँ से स्वामी विवेकानंद, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, रवींद्रनाथ ठाकुर और नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे महापुरुषों ने भारतीय राष्ट्रवाद को नई दिशा दी। 'वंदे मातरम्' का उद्घोष भी इसी भूमि से निकला। इसलिए जब बंगाल में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक अस्मिता की चर्चा होती है, तो वह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि भावनात्मक और ऐतिहासिक संदर्भ भी ग्रहण कर लेता है। भाजपा ने इसी ऐतिहासिक चेतना को पुनः जागृत करने का प्रयास किया। दुर्गापूजा, रामनवमी, हनुमान जयंती और हिंदू धार्मिक प्रतीकों को लेकर जिस प्रकार की राजनीतिक बहसें पिछले वर्षों में सामने आईं, उन्होंने हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग को यह महसूस कराया कि उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां राजनीतिक विवाद का विषय बन रही हैं। परिणामस्वरूप एक बड़ा वर्ग अपनी पहचान के प्रश्न पर अधिक मुखर हुआ।

पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से अल्पसंख्यक वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती रही है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि ममता बनर्जी सरकार ने संतुलित शासन के बजाय तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। चाहे इमाम भत्ता का मुद्दा हो, धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासनिक निर्णय हों या सीमावर्ती जिलों में बदलता जनसांख्यिकीय संतुलन-इन सभी विषयों ने धीरे-धीरे हिंदू समाज के भीतर असंतोष को जन्म दिया। यह असंतोष केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी था। अनेक लोगों को यह लगने लगा कि राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता का अभाव है। भाजपा ने इसी भावना को राजनीतिक रूप दिया। उसने यह संदेश देने का प्रयास किया कि उसकी राजनीति केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि 'सांस्कृतिक सुरक्षा' स्थापित करने की राजनीति है। यही कारण है कि चुनाव प्रचार के दौरान 'जय श्रीराम' जैसे नारे केवल धार्मिक उद्घोष नहीं रहे, बल्कि वे एक प्रकार के राजनीतिक प्रतिरोध और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक बन गए।

इस चुनाव में हिंदी भाषी मतदाताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में हिंदी भाषी समाज का प्रभाव बढ़ा है। यह वर्ग लंबे समय से स्वयं को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करता रहा था। भाजपा ने इस वर्ग को संगठित करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि इस चुनाव को केवल 'हिंदी बनाम बंगाली' के दृष्टिकोण से देखना भी उचित नहीं होगा। वस्तुतः भाजपा ने हिंदी भाषी और स्थानीय हिंदू समाज के बीच एक वैचारिक सेतु बनाने का प्रयास किया। उसने यह संदेश दिया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर है। यही कारण है कि बंगाल के अनेक क्षेत्रों में भाजपा को व्यापक समर्थन मिला। पश्चिम बंगाल कभी वामपंथ का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। वर्ग-संघर्ष, श्रमिक राजनीति और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा यहाँ की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा रही। लेकिन समय के साथ यह विचारधारा जमीन से कटती चली गई। वामपंथी दल जनता की नई आकांक्षाओं, युवाओं की उम्मीदों और बदलते सामाजिक यथार्थ को समझने में असफल रहे। आज का युवा केवल वैचारिक भाषण नहीं चाहता- वह रोजगार, सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्मान और विकास चाहता है। यही कारण है कि वामपंथ धीरे-धीरे राजनीतिक हाशिये पर पहुँच गया। भाजपा ने इस खाली स्थान को भरते हुए स्वयं को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में स्थापित किया।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता को अनेक लोग डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों से भी जोड़कर देख रहे हैं। डॉ. मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विभाजनकारी राजनीति का विरोध किया और राष्ट्रीय एकात्मता को सर्वोपरि माना। बंगाल की राजनीति में भाजपा का उभार कहीं न कहीं उसी विचारधारा की पुनर्स्थापना के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि बंगाल अब केवल क्षेत्रीय राजनीति का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि वह पुनः राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व करेगा। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या इन चुनाव परिणामों को 'हिंदू पुनर्जागरण' कहा जा सकता है? इसका उत्तर पूरी तरह सरल नहीं है, किंतु इतना स्पष्ट है कि हिंदू समाज के भीतर अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर एक नई जागरूकता अवश्य उत्पन्न हुई है। यह जागरूकता केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीतिक अभिव्यक्ति का भी रूप ले रही है। हालांकि किसी भी लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक चेतना सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों के साथ संतुलित रहे। यदि पहचान की राजनीति संवाद और समावेशिता के बजाय टकराव का रूप लेती है, तो वह लोकतंत्र के लिए चुनौती बन सकती है। इसलिए बंगाल के इस परिवर्तन को केवल विजय उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी और आत्ममंथन के अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। भाजपा की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल अब राजनीतिक रूप से 'अपवाद' नहीं रहा। यहाँ भी वही प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं जो देश के अन्य हिस्सों में प्रभावी हैं-सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सामाजिक संतुलन। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। यदि भाजपा वास्तव में बंगाल में एक नए युग की शुरूआत करना चाहती है, तो उसे केवल वैचारिक नारों तक सीमित नहीं रहना होगा। उसे रोजगार, उद्योग, शिक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर ठोस कार्य करना होगा। बंगाल की धरती ने हमेशा भारत को विचार, साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रवाद की नई दिशा दी है। आज फिर इतिहास एक नए मोड़ पर खड़ा है। आने वाला समय तय करेगा कि यह परिवर्तन केवल राजनीतिक लहर साबित होगा या वास्तव में बंगाल के सांस्कृतिक और वैचारिक पुनर्जागरण का आधार बनेगा।

संपादकीय

हिंसा अस्वीकार्य

छिटपुट हिंसा की घटनाओं के बावजूद पश्चिम बंगाल में कमोबेश शांतिपूर्ण मतदान हुआ था। लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हो रही हिंसा की घटनाएं परेशान करने वाली हैं। भाजपा व टीएमसी के कुछ समर्थकों में हिंसक झड़पों के अलावा राज्य में पार्टी के अगु?वा रहे सुवेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या चौंकाने वाली है। इससे दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ा है। राज्य में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार सुवेंदु अधिकारी का दावा है कि रथ की हत्या उनके करीबी होने के कारण की गई है। वहीं चंद्रनाथ के परिजनों का आरोप है कि यह हत्या ममता बनर्जी की भवानीपुर में अधिकारी से हुई हार का बदला लेने के लिये की गई है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान कुछ भाजपा व टीएमसी कार्यकताओं की भी हत्या की गई है। दरअसल, पंद्रह साल से सत्ता में काबिज रही टीएमसी पर भाजपा की बड़ी जीत ने दोनों पार्टियों के बीच तनाव को बढ़ाया है। यही वजह है कि भारतीय चुनाव आयोग पर हमलावर होते हुए ममता बनर्जी ने केवल चुनाव परिणामों को ही खारिज नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने तक से मना कर दिया। उनकी इस घोषणा ने लंबे समय से जारी टकराव को बढ़ाने का काम ही किया। इस घटनाक्रम से टीएमसी कार्यकताओं को आक्रामक होने का मौका मिला। निश्चय ही यह स्थिति राज्य के हित में नहीं कही जा सकती। राज्य में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किए जाने की जरूरत है। कायदे में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ममता को सदाशयता का परिचय देते हुए कार्यकताओं से शांत रहने की अपील राज्य हित में करनी चाहिए। यही लोकतंत्र का तकाजा भी है। वहीं दूसरी ओर, भाजपा को भी अपने कार्यकताओं को शांत रहने के लिये प्रेरित करना चाहिए। उन्हें चुनाव परिणाम सामने आने के बाद हिंसा से परहेज करना चाहिए। यही लोकतंत्र की प्रतिष्ठा भी है। यह विडंबना ही है कि चुनाव आयोग द्वारा राज्य के अधिकारियों को विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश देने के बाद भी दोनों दलों के कार्यकताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। ऐसी स्थिति में राज्य पुलिस को हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए, केंद्रीय बलों के साथ कानून व्यवस्था बहाल करने के लिये मिलकर काम करना चाहिए। यूं तो पूरे राज्य में ही, अन्यथा खासकर संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ायी जानी चाहिए। हिंसक वारदातों व तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल से संबद्धता की परवाह किए बिना उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना वक्त की जरूरत है। भाजपा व टीएमसी को अपने कार्यकताओं से संयम बरतने को कहना चाहिए। वास्तव में अतीत में हिंसा का लंबा इतिहास रखने वाले पश्चिम बंगाल को अब नये सिरे से शुरूआत करके विकास के पथ पर लौटना चाहिए। यह निर्विवाद सत्य है कि किसी भी हिंसा की कीमत आखिर आम जनता को ही चुकानी पड़ती है। यदि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि राज्य की राजनीति में अपराध जगत से जुड़े व दबंग किस्म के लोग दखल देते रहे हैं। कभी वे राजनीतिक दलों के लिए बूथ लूटने का काम किया करते थे। एक समय वामपंथी सरकार में दखल रखने वाले ये लोग कालांतर तृणमूल कांग्रेस के लिये काम करने लगे थे।

चिंतन-मनन

दौलत की चाह

संत जुनैद की एक झलक पाने और उनसे ज्ञान की बातें सुनने के लिए लोग बेकरार रहते थे। पर जुनैद दुनियावी चीजों से तटस्थ और निर्लिप्त रहते थे। वह खाने-पीने और अपने कपड़े से भी बेपरवाह रहते थे। वह हर समय घूमते रहते थे। जहां भी रात होती वह वहीं टिक जाते। एक बार वह एक बड़े शहर के बाहर रुके तो शहर के जाने-माने एक सेठ उनके दर्शन के लिए आ पहुंचे। वह अपने साथ ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए थे। उन्होंने उसकी थैली जुनैद के चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जुनैद ने थैली पर नजर डाली, फिर मुस्कराते हुए पूछा-क्या इसके अलावा भी आपके पास और दौलत है? सेठ जी ने प्रसन्न होकर सोचा कि जुनैद को और भी धन चाहिए। सेठ ने कहा-मेरे पास तो इससे कई गुना धन-संपत्ति और है। सेठ ने पूछा-क्या आप और दौलत पाने की ख्वाहिश रखते हैं? सेठ ने कहा- हां, हां क्यों नहीं, अब इतने से क्या होता है। थोड़ी और दौलत मिल जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी।

जुनैद ने कहा- तब तो ये दौलत भी आप ही रख लीजिए। इसकी असल जरूरत तो आपको ही है। आपको और धन-संपत्ति चाहिए। इतना आप मुझे ही दे देंगे तो आपका खजाना थोड़ा खाली हो जाएगा। जिसके पास सब कुछ हो लेकिन और पाने की चाह हो, उसके दान का भी कोई अर्थ नहीं है। यह सुनकर सेठ जी लज्जित हो गए। उन्होंने जुनैद से वादा किया कि वह अब और दौलत के पीछे नहीं भागेंगे

आवश्यकता है

आवश्यकता है दैनिक सब का सपना समाचार पत्र को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर व जिला स्तर पर संवाददाताओं की इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।

9456884327/8218179552

क्या राज्यपाल संवैधानिक मयार्दा से ऊपर हैं?

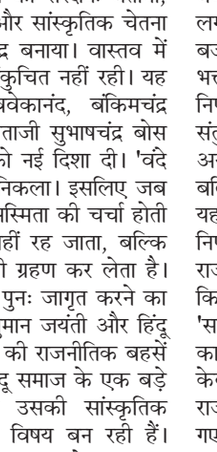

सनत जैन

तमिलनाडु में चुनाव परिणाम आने के बाद उत्पन्न राजनीतिक स्थिति ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसके साथ ही सरकार बनाने का दावा विजय राज्यपाल के सम्मुख कर चुके हैं। कांग्रेस के समर्थन के बाद यह संख्या 113 तक पहुंच गई। बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। इसके बावजूद राज्यपाल द्वारा सरकार गठन के लिए आमंत्रित न करना केवल राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि संवैधानिक परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन गया है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रमुख माना गया है, न कि राजनीतिक निर्णायक। संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छा सर्वोपरि होगी। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, तब सबसे बड़े दल या गठबंधन को सरकार बनाने का अवसर देना एक स्थापित संवैधानिक परंपरा बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि बहुमत का परीक्षण विधानसभा के भीतर होना चाहिए, राजभवन में नहीं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और उत्तराखंड जैसे मामलों में न्यायपालिका ने बार-बार यही सिद्धांत दोहराया है।

वर्तमान में तमिलनाडु का मामला इसलिए अधिक गंभीर माना जा रहा है क्योंकि चुनाव नतीजों के मुताबिक दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली अन्य पार्टियों ने सरकार बनाने का दावा ही प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल को शपथ ग्रहण का अवसर न देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से बाधित करने जैसा प्रतीत होता है। राज्यपाल यदि यह कहें कि पहले पूर्ण बहुमत साबित करें, तभी शपथ दिलाई जाएगी, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर विधानसभा में बहुमत परीक्षण की परंपरा का महत्व क्या रह जाएगा? पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों में राज्यपाल और निर्वाचित सरकारों के बीच टकराव बढ़ा है। विपक्ष शासित राज्यों में विधेयकों को महीनों और कभी-कभी वर्षों तक लंबित रखना, सरकारों के प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप तथा राजनीतिक बयानबाजी ने इस पद की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। संविधान निमार्ताओं ने राज्यपाल पद की कल्पना केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए की थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह पद कई बार राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनता दिखाई देता है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यदि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग न्यायालयों द्वारा स्थापित सिद्धांतों की भी अनदेखी करने लगें, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होने लगता है। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने से नहीं चलता; वह संवैधानिक मयार्दा, संस्थागत निष्पक्षता और स्थापित परंपराओं के सम्मान पर टिकता है। यदि निर्वाचित सरकारों के गठन में भी व्यक्तिगत विवेक या राजनीतिक झुकाव हावी होने लगे, तो यह संघीय ढांचे के लिए खतरे का संकेत होगा। ऐसे समय में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट करना होगा कि राज्यपाल का विवेक सीमित है और वह संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के जनादेश की होती है। उस जनादेश का सम्मान करना ही संविधान की वास्तविक आत्मा है।

संजय राउत ने डोनाल्ड ट्रंप को पत्र में जो कुछ लिखा है उससे विपक्षी नेताओं की देशभक्ति पर सवाल उठ गया है

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं अब केवल राजनीतिक असहमति तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े करती दिखाई दे रही हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखना और ममता बनर्जी द्वारा अंतरराष्ट्रीय अदालत जाने की चेतावनी देना इसी प्रवृत्ति का ताजा उदाहरण है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के आंतरिक मामलों को विदेशी शक्तियों और वैश्विक मंचों तक ले जाना लोकतंत्र की रक्षा है या फिर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास?

हम आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखे अपने पत्र में पश्चिम बंगाल चुनावों को भय, दबाव और कथित धांधली से प्रभावित बताया। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर भी आरोप लगाए। हैरानी की बात यह है कि यह सब उस समय कहा जा रहा है जब भारत का चुनाव आयोग विश्व की सबसे विश्वसनीय और विशाल चुनावी संस्थाओं में गिना जाता है। यदि किसी दल को चुनाव परिणाम स्वीकार नहीं हैं, तो उसके लिए न्यायपालिका, जन आंदोलन और संवैधानिक प्रक्रियाएं मौजूद हैं। फिर विदेशी राष्ट्रपति को पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

क्या भारत इतना कमजोर लोकतंत्र है कि यहां के चुनावों का फैसला विदेशी नेताओं की राय से तय होगा? क्या विपक्ष यह संदेश देना चाहता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर उसे भरोसा नहीं है? यदि हर हार के बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया जाएगा, तो इससे दुनिया में भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा?

इस पूरे विवाद में ममता बनर्जी का बयान भी कम गंभीर नहीं है। चुनाव हारने के बाद उनका यह कहना कि वह अंतरराष्ट्रीय अदालत तक जाएंगी, कई सवाल खड़े करता है। क्या किसी राज्य के चुनावी परिणाम को लेकर संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक संस्था में जाने की बात करना भारत की संप्रभुता पर प्रश्नचिह्न लगाने जैसा नहीं है? जब देश का संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग मौजूद हैं, तब विदेशी अदालतों की चर्चा क्यों? दरअसल यह वही राजनीति है जिसमें जब तक सत्ता हाथ में रहे तब तक संस्थाएं निष्पक्ष लगती हैं, लेकिन हार मिलते ही चुनाव आयोग, सुरक्षा बल, न्यायपालिका और लोकतंत्र सब कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। यह प्रवृत्ति केवल राजनीतिक असंतोष नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करने का प्रयास भी मानी जा सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या विपक्षी दल अपनी राजनीतिक हार को स्वीकार करने का साहस खो चुके हैं? क्या लोकतंत्र केवल तब तक सही है जब तक परिणाम उनके पक्ष में आएं? यदि हर चुनाव के बाद विदेशी शक्तियों से हस्तक्षेप की मांग की जाएगी, तो क्या यह देश की आंतरिक संप्रभुता के खिलाफ कदम नहीं माना जाएगा?

भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां सत्ता परिवर्तन चुनावों के माध्यम से होता है, अदालतें स्वतंत्र हैं और मीडिया पूरी तरह सक्रिय है। ऐसे में विदेशी नेताओं और अंतरराष्ट्रीय मंचों को भारत के घरेलू राजनीतिक विवादों में घसीटना न केवल राजनीतिक अपरिपक्वता दशार्ता है, बल्कि यह देश की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है।

राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन देश की छवि और संस्थाओं की विश्वसनीयता से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। देखा जाये तो लोकतंत्र में हार और जीत दोनों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी लोकतांत्रिक मयार्दा होती है। लेकिन संजय राउत जैसे लोग जोकि खुद करोड़ों के घोटाले के आरोप से जुड़े हैं और जेल काट चुके हैं, वह भारत के लोकतंत्र की शुचिता और जनमत की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। यहां एक सवाल यह भी उठता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गयी बधाई विपक्ष को इतनी चुभ क्यों रही है?

साथ ही संजय राउत भारतीय लोकतंत्र को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि स्वयं अमेरिका में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर कितने गंभीर सवाल उठ चुके हैं। दुनिया ने देखा कि वर्ष 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव परिणाम स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। चुनावी धांधली के आरोपों को लेकर उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल पर हमला तक कर दिया था, जिसे अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना गया। उस घटना में हिंसा हुई, कई लोग घायल हुए और पूरे विश्व ने अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था को संकट में देखा। इतना ही नहीं, ट्रंप लगातार अमेरिकी चुनाव प्रणाली, न्याय व्यवस्था और मीडिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में भारतीय नेताओं द्वारा अमेरिका को सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र का प्रमाण पत्र बांटने वाला देश मान लेना अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। भारत में चुनाव करोड़ों मतदाताओं की भागीदारी से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होते हैं और सत्ता परिवर्तन भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। इसलिए विदेशी नेताओं से शिकायत करने से पहले विपक्ष को यह भी देखना चाहिए कि जिन देशों की ओर वह उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, वहां स्वयं लोकतंत्र कितनी चुनौतियों से गुजर रहा है।

विश्व रेड क्रॉस दिवस पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित

अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के जिला संयुक्त चिकित्सालय में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संयुक्त उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेन्द्र सिंह तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अश्वनी कुमार भण्डारी द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान उपस्थित रक्तदाताओं को बताया गया कि रक्तदान से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। दान किए गए रक्त की पूर्ति लगभग एक माह में स्वयं हो जाती है और शरीर नया रक्त बनाता है, जिससे दाता को नई ऊर्जा मिलती है। जिला अस्पताल में स्थापित ब्लड बैंक जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, आयुष्मान कार्डधारकों, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों, सड़क दुर्घटना के घायल मरीजों तथा कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराता है। अस्पताल प्रतिदिन 8 से 10 यूनिट रक्त भर्ती मरीजों को मुहैया कराता है।

हालांकि समय-समय पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन अस्पताल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त संग्रह नहीं हो पा रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए क्षेत्र में अधिक से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित करने और विभिन्न संगठनों के सहयोग की अपील की गई।इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. एस.के. चौधरी, सचिव नेत्र विशेषज्ञ डॉ. पंकज बादल, सर्जन डॉ. शकील फारूखी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. के.एस. सैनी, ऑर्थो सर्जन डॉ. रमेश सैनी, डॉ. रविन्द्र सिंह, डॉ. आर.के. सिरोही, समाजसेवी राम अवतार कपसिया सहित कई चिकित्सक और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

अमरोहा पहुंचे सुभासपा के प्रदेश उपाध्यक्ष , कार्यकताओं ने फूलमालाओं से किया स्वागत

अमरोहा (सब का सपना):- सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर द्वारा बलराज प्रजापति को पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद संगठन में उत्साह का माहौल बना हुआ है। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अमरोहा पहुंचने पर सुभासपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्यपाल तोमर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके आवास पहुंचे जहां फूलमालाओं से लादकर व मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष बलराज प्रजापति ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूजी ओमप्रकाश राजभर ने उन पर जो भरोसा जताया है वह उस विश्वास को पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी के साथ निभाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सुभासपा हमेशा समाज के शोषित व वंचित वर्गों की आवाज उठाने वाली पार्टी रही है और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संगठन विस्तार को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा तथा गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकताओं की मेहनत और जनता के सहयोग से पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। प्रदेश सरकार में सुभासपा की भागीदारी से समाज के कमजोर वर्गों को न्याय और सम्मान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। बलराज प्रजापति ने कहा कि वह क्षेत्र की जनता की समस्याओं को भी मजबूती से उठाने का कार्य करेंगे तथा पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सुभासपा जिलाध्यक्ष सत्यपाल तोमर ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर द्वारा बलराज प्रजापति को प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना संगठन के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि श्री प्रजापति लंबे समय से पार्टी की नीतियों और संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

उनकी कार्यशैली और जनसंपर्क का लाभ निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद संगठन को नई मजबूती मिलेगी और कार्यकताओं में भी उत्साह का संचार होगा। उन्होंने कहा कि सुभासपा लगातार प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार कर रही है और पार्टी की नीतियों को जनता का समर्थन मिल रहा है। आने वाले समय में पार्टी और अधिक मजबूती के साथ जनता के बीच कार्य करेगी स्वागत करने वालों में पंडित राम अवतार शर्मा मंडल उपाध्यक्ष मंत्री प्रतिनिधि रामपुर आदेश अमरोही कोषाध्यक्ष डॉ जगत सिंह गुर्जर जिला महासचिव पवन कुमार पंडित योगेंद्र शर्मा, विवेक कुमार, जुबैर अहमद इस्लामउद्दीन इदरीसी आदि मौजूद रहे।

जे0 एस0 हिन्दू इण्टर कॉलेज में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को किए बैग वितरित

अमरोहा (सब का सपना):- शहर के जे0 एस0 हिन्दू इण्टर कॉलेज में प्रबंध समिति के अध्यक्ष अनिल स्वरूप टंडन और प्रबंधक पंकज गुप्ता ने गरीब और जरूरतमंद लगभग 50 छात्र छात्राओं को बैग वितरित किए। इससे पूर्व भी प्रबंध समिति गरीब और असहाय बच्चों की मदद करती रही है।

प्रबंध समिति के अध्यक्ष अनिल स्वरूप टंडन ने कहा कि कोई छात्र या छात्रा अगर अपनी पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण आगे जारी रखने में असमर्थ है तो उसकी हर संभव मदद की जाएगी।

विद्यालय के प्रबंधक पंकज गुप्ता ने कहा कि गरीब बच्चों को कापी, पुस्तकें आदि या फीस में जो भी सहायता होगी, उन्हें दी जाएगी। घर की आर्थिक परेशानी की वजह से किसी भी छात्र या छात्रा की पढ़ाई अधूरी नहीं रहेगी। बिना माता या पिता अथवा दोनों के न होने पर उन बच्चों को किताबो की व्यवस्था विद्यालय स्तर से कराई जाएगी।

प्रधानाचार्य डॉ0 जी0 पी0 सिंह ने बताया कि मेधावी और होनहार छात्र छात्राओं की सहायता के लिए हमारा विद्यालय सदैव से अग्रणी रहा है। प्रबंध समिति और विद्यालय प्रशासन ने विद्यालय में छात्र छात्राओं की हर सुविधाओं का ध्यान रखा है। अच्छी शिक्षा के साथ साथ एन0 सी0 सी0, स्काउट्स गाइड्स तथा राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी योजनाएं भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में उपलब्ध है। इस वर्ष से विद्यालय में कौशल विकास योजना के तहत कक्षा 9 एवं 11 के छात्र छात्राओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड में शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। जिसमें इस वर्ष जुलाई माह से इसकी व्यवस्था होगी। कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार ने किया डॉ0 राजेश राजपूत ने सहयोग किया।

हसनपुर 42 विधानसभा क्षेत्र के दरियापुर गांव में पीडीए पंचायत का किया गया आयोजन

हसनपुर/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के हसनपुर 42 विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दरियापुर तुगन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार व गंगेश्वरी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खड्गवंशी के नेतृत्व मे पीडीए पंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र सिंह खड़कवंशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हर महिला को सम्मान निधि के रूप में 40000 रुपये प्रति वर्ष और 300 यूनिट बिजली बिल हर महीने घर-घर फ्री दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पेंशन योजना के तहत सभी धर्मों और वर्गों का सम्मान किया जाएगा। इस मौके पर ब्लाक प्रमुख गंगेश्वरी राजेंद्र सिंह खड्गवंशी, प्रेमपाल सिंह खड़कवंशी, ऋषिपाल सिंह खड़कवंशी, बूथ अध्यक्ष प्रकाश सिंह खड़कवंशी, तान सिंह खड़कवंशी, सतीश कुमार, हेतराम सिंह खड़कवंशी, ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह जाटव, चरन सिंह नेता जी, विजेंद्र सिंह खड़कवंशी, एडवोकेट दानवीर सिंह खड़कवंशी, भूरा सिंह खड़कवंशी, राजपाल सिंह खड़कवंशी, धर्मवीर सिंह खड़क बंशी, नरेश सिंह खड़कवंशी, सत्य प्रकाश खड़क वंशी, कुंवर पाल सिंह खड़कवंशी, सोमपाल सिंह, प्रेम सिंह, राजवीर सिंह, राजेश सिंह, बुद्धन सिंह, नन्नू सिंह, धर्मपाल सिंह, भोजराम सिंह, शीशपाल सिंह, राम अवतार डीलर साहब, मुंशीलाल सिंह, मुकेश सिंह, हरचरण सिंह खड़कवंशी, गजराम सिंह जाटव, छोटेलाल सिंह, प्रेम सिंह, नौबत सिंह, प्रताप सिंह खड़कवंशी, रामचरण जाटव, चन्दकिरन प्रजापति आदि सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

मंडी धनौरा में लेखपाल संघ द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा,15 मई को होगा मतदान,7 पदों पर चयन

धनौरा/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के मंडी धनौरा में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसका मतदान आगामी 15 मई 2026 को तहसील सभागार में किया जाएगा। यह चुनाव सात पदों पर लड़ा जाएगा जिसमें क्षेत्र के लेखपाल नयी कार्यकारणी का चयन करेंगे।

बता दें कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अमरोहा तहसील के लेखपाल प्रशांत गुर्जर को मुख्य चुनाव अधिकारी और हसनपुर तहसील के लेखपाल दिनेश कुमार को उपचुनाव अधिकारी बनाया गया है।मतदान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक तहसील सभागार में होगा, जिसके तुरंत बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस चुनाव में कुल सात महत्वपूर्ण पदों पर पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा।इनमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष और ऑडिटर (लेखा परीक्षक) के पद शामिल हैं।वर्तमान में संघ की कमान विकास यादव के हाथों में है, जो वर्ष 2022 से लगातार दो कार्यकालों से अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। पिछले चुनाव में उन्हें निर्विरोध चुना गया था। इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या विकास यादव अध्यक्ष पद पर अपनी हैट्रिक पूरी कर पाते हैं या संगठन को नया नेतृत्व मिलता है।धनौरा उपशाखा के कुल 68 लेखपाल इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दो साल के अंतराल पर होने वाला यह चुनाव लेखपालों की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तहसील परिसर में प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, चुनाव शांतिपूर्ण और नियमानुसार संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है।

अब खास दुकानों से किताबें व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं होंगे अभिभावक

प्रशासन ने दिए निर्देश,सभी विद्यालयों को RTE नियमों का पालन करना अनिवार्य

धनौरा/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के मंडी धनौरा में अब अभिभावकों को निजी विद्यालयों की किताबें एवं यूनिफॉर्म किसी एक दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा ,क्योंकि प्रशासन की तरफ से अब निजी विद्यालयों के लिए यह आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सभी विद्यालय आरटीई एक्ट 2009 के नियमों के तहत संचालित होंगे। स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वह पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाना ही सुनिश्चित करें। खंड शिक्षा अधिकारी धनौरा ने विकास क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त मदरसे एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को कड़े निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी विद्यालय अभिभावकों पर किसी विशेष दुकान से कोर्स खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाएगा।

बता दें कि यह कार्रवाई भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के कार्यकताओं द्वारा उठाए गए विरोध के बाद अमल में लाई गई है। बीती 28 अप्रैल को मयंक धारीवाल एवं सौबीर सिंह के नेतृत्व में कार्यकताओं ने ब्लॉक परिसर में प्रदर्शन कर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की शिकायत की थी।कार्यकताओं का आरोप था कि स्कूल प्रबंधन अपनी तय दुकानों से ही सामान खरीदने का दबाव बना रहे हैं, जिससे अभिभावकों का आर्थिक शोषण हो रहा है।उपजिलाधिकारी (SDM) धनौरा के निदेर्शों के क्रम में जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विद्यालय आर.टी.ई. (RTE) एक्ट 2009 के नियमों के तहत ही संचालित होंगे। स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे पाठ्यक्रम में एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) की पुस्तकें लगाना सुनिश्चित करें,साथ ही किताबों और यूनिफॉर्म के संबंध में पूरी जानकारी लिखित रूप में सार्वजनिक करनी होगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने एक अनोखा कदम उठाया है।अगले तीन दिनों के भीतर प्रत्येक विद्यालय को अपने मुख्य द्वार की दीवार पर जिले के महत्वपूर्ण अधिकारियों के मोबाइल नंबर पेंट करवाने होंगे, ताकि अभिभावक सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।इन अधिकारियों के नंबर इस प्रकार हैं: एसडीएम धनौराः 9454416930, जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS): 9454457307, बीएसए अमरोहाः 9453004181, आरटीओ अमरोहाः 8005441178।खंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी विद्यालय द्वारा इन निदेर्शों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित संस्थान के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रजबपुर में बाइक सवार युवक से मारपीट, मुकदमा दर्ज

रजबपुर/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के थाना रजबपुर क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

बता दें कि मामले में प्राप्त जानकारी के मुताबिक रजबपुर निवासी खलील अहमद के पुत्र शारिक अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 6 मई को सुबह 9 बजे गजरौला अपने निजी काम से गए थे। काम खत्म कर रात करीब 9 बजे वह गजरौला से घर लौट रहे थे। नीलकंठ स्टार होटल के पास पहुंचने पर उन्होंने अपनी बाइक रोककर अपनी होने वाली पत्नी से बात करना शुरू किया।इसी दौरान शकरपुर अंडर पास की ओर से तीन अज्ञात लड़के आए। उन्होंने कुछ दूरी पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और शारिक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। जब शारिक ने इसका विरोध किया, तो युवकों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इस घटना में शारिक घायल हो गए।मारपीट के बाद तीनों अज्ञात युवक शारिक को धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित शारिक ने तत्काल मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर 7 मई को आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।

थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

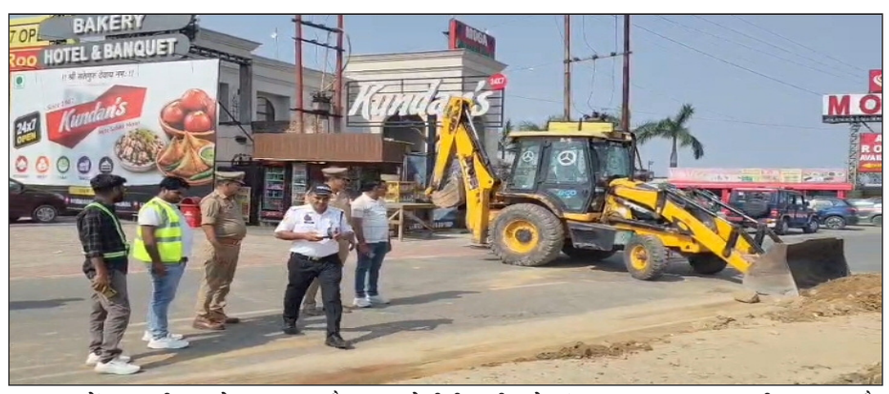

यातायात पुलिस का बड़ा अभियान, ओवरस्पीड वाले 110 वाहनों समेत 340 चालान,10 अवैध कट बंद

गजरौला/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। ओवरस्पीड चलने वाले 110 वाहनों समेत कुल 340 वाहनों के चालान किए गए। गजरौला में हाईवे के 10 अवैध कट भी बंद कराए गए।

बता दें कि अमरोहा एसपी लखन सिंह यादव के निर्देश पर 8 मई 2026 को यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरस्पीड और नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।यातायात उपनिरीक्षक अनुज कुमार मलिक ने बताया कि तेज गति से वाहन चलाने वाले 110 वाहनों के चालान किए गए। नो पार्किंग में खड़े वाहनों समेत कुल 340 वाहनों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई।इसके अलावा गजरौला क्षेत्र में हाईवे पर बने अवैध कटों के खिलाफ भी संयुक्त अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस, थाना गजरौला और ठलअककी संयुक्त टीम ने 10 अवैध कट जेसीबी मशीन से बंद कराए।टीएसआई अनुज कुमार मलिक ने बताया कि ये अवैध कट सड़क हादसों की बड़ी वजह बन रहे थे। टीम ने स्थानीय लोगों को चेतावनी दी कि हाईवे पर अनधिकृत कट बनाना कानूनी अपराध है। दोबारा ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।पुलिस ने वाहन चालकों से हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने और गति सीमा का पालन करने की अपील की है।

सक्षम संगठन की बैठक में जिला कार्यकारिणी का गठन, संत सूरदास जयंती कार्यक्रम पर बनी रणनीति

चन्दौसी/सम्भल(सब का सपना):- समदृष्टि क्षमताविकास एवं अनुसंधान मण्डल (सक्षम) की मेरठ प्रान्त अंतर्गत जिला सम्भल इकाई की परिचय एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर एक महत्वपूर्ण योजना बैठक नगर चन्दौसी में सम्पन्न हुई। बैठक में संगठन के उद्देश्य, विस्तार एवं आगामी सामाजिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला कार्यकारिणी के गठन पर विचार-विमर्श करते हुए विभिन्न पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इसमें मंतेश वार्ष्णेय को जिलाध्यक्ष, प्रतिभा चौधरी को जिला महिला प्रमुख, डोली शर्मा को जिला कार्यकारिणी सदस्य महिला, डॉ. गौरव बंसल को जिला उपाध्यक्ष, रोहित वार्ष्णेय को जिला कोषाध्यक्ष, शुभम अग्रवाल को जिला प्रचार

प्रमुख तथा अभिनव शर्मा, देवेन्द्र गुप्ता मोनू, रितिक वार्ष्णेय एवं आदेश कुमार को जिला कार्यकारिणी सदस्य के दायित्व सौंपे गए। जिला सचिव अनुज वार्ष्णेय अन्नू ने जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही पूरे जनपद में अन्य दायित्ववान कार्यकर्ताओं की भी घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर प्रान्त संगठन मंत्री आशुतोष ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सक्षम संगठन के उद्देश्य, महत्व एवं समाज में उसकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संगठन का मूल उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनके आत्मसम्मान, स्वावलंबन एवं अधिकारों को सशक्त बनाना है। संगठन सेवा कार्यों के साथ-साथ समाज में जागरूकता फैलाकर सकारात्मक सोच विकसित करने का कार्य भी कर रहा है। बैठक में वार्षिक रूप से प्रस्तावित छह प्रमुख कार्यक्रमों में से एक ह्यसंत सूरदास जयंती आयोजन को लेकर विशेष चर्चा हुई।

निर्णय लिया गया कि यह कार्यक्रम 9 मई को चन्दौसी के रामबाग रोड स्थित वृद्ध आश्रम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धजनों के स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण हेतु विभिन्न चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच एवं परामर्श की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में उपस्थित सभी कार्यकताओं ने संगठन को मजबूत करने एवं सामाजिक सेवा के कार्यों को गति देने का संकल्प लिया।

मेधावी छात्र सम्मान समारोह में प्रतिभाओं का हुआ सम्मान, एसडीएम नीतू रानी ने बढ़ाया उत्साह

चंदौसी/सम्भल(सब का सपना):- जगदीश शरण सर्राफ सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज हनुमानगढ़ी, चंदौसी में शुक्रवार को मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चंदौसी की एसडीएम नीतू रानी उपस्थित रहीं। समारोह में विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी, शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इसके बाद शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

अपने संबोधन में एसडीएम नीतू रानी ने छात्रों को निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, लगन और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने की सीख भी दी।

विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरपाल सिंह ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों के भीतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों ने भी मेधावी छात्रों की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अभिभावक के रूप में उपस्थित डॉ. निवास यादव ने छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया तथा विद्यालय परिवार की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों के अनुशासन एवं परिश्रम की प्रशंसा करते हुए उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर रामौतार शर्मा (संरक्षक), एडवोकेट छत्रपाल यादव (उपाध्यक्ष), सुनील कुमार (प्रबंधक), प्रतीक अग्रवाल (उपप्रबंधक), डॉ. वीरेश (कोषाध्यक्ष), पंकज सर्राफ (सदस्य), शिवम यादव, सुरेश चंद्र यादव (प्रभारी), डॉ. टी.एस. पाल (समाजसेवी एवं मीडिया प्रभारी), हदयेश यादव एडवोकेट सहित विद्यालय परिवार एवं अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ आचार्य जगपाल ने किया।

बाबा गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार, अवैध तमंचे व कारतूस बरामद

एक लाख की रंगदारी मांगने और हवाई फायरिंग के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जुनावई/सम्भल(सब का सपना):- सम्भल पुलिस के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के आदेश पर चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना जुनावई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) मनोज कुमार रावत एवं क्षेत्राधिकारी गुन्नौर आलोक सिद्धू के निर्देशन में पुलिस टीम ने तथाकथित बाबा गैंग के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार थाना जुनावई में 6 मई को रामपाल पुत्र भूदेव निवासी दवथरा हिमांचल द्वारा तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि 3 मई को अंकित, अवधेश और उनके 10-15 साथियों ने उससे एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। रुपये न देने पर आरोपियों ने हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी दी थी। तहरीर

के आधार पर थाना जुनावई में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी भागने की फिराक में हैं। इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार की रात जुनावई शनिवार बाजार से सराय ब्राह्मण जाने वाले रास्ते पर छापेमारी कर आरोपी अंकित उर्फ दीपेन्द्र पुत्र राकेश उर्फ जयवीर और अवधेश उर्फ उपदेश कुमार पुत्र मुकेश को बोलेरो गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में दोनों के कब्जे से दो अवैध तमंचे 315 बोर और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं।

गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने उनके अन्य साथियों प्रिंस पुत्र दिनेश शर्मा, कुलदीप जडेजा पुत्र बाबूराम, अमन शर्मा पुत्र मनोज शर्मा और सुरेन्द्र पुत्र सरवन को भी सराय ब्राह्मण तिराहे से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी बाबा गैंग के सदस्य हैं और उनके गैंग में 25-30 युवक शामिल हैं। गैंग के सदस्य व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाबा नाम से ग्रुप बनाकर जुड़े हुए हैं। आरोपी लोगों को डराकर और धमकाकर पैसे वसूलते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि रामपाल से भी एक लाख रुपये की मांग की गई थी और पैसे न देने पर डराने के लिए हवाई फायरिंग की गई थी।

पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर आगे

संसाधनों की मांग को लेकर पंचायत सहायकों ने उठाई आवाज, सौंपा ज्ञापन

चन्दौसी/सम्भल(सब का सपना):- ब्लॉक बनियाखेड़ा क्षेत्र के पंचायत सहायकों ने कार्य संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को ज्ञापन सौंपते हुए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। पंचायत सहायकों का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल कार्यों का लगातार बढ़ता दबाव संसाधनों के अभाव में प्रभावित हो रहा है।

ज्ञापन में पंचायत सहायकों ने बताया कि उन्हें पोर्टल प्रविष्टियां, प्रमाण पत्रों से संबंधित कार्य, योजनाओं का ऑनलाइन संचालन, रेट्रो फिटिंग तथा अभिलेखों के संधारण सहित अनेक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। लेकिन आवश्यक उपकरण और सुविधाएं न होने के कारण कार्य करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

पंचायत सहायकों ने मांग की कि शासकीय कार्यों के सुचारु संचालन हेतु आधुनिक 5ऋ मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएं, जिनमें 8 जीबी रैम एवं 256 जीबी स्टोरेज क्षमता हो। इसके अलावा प्रत्येक माह इंटरनेट एवं मोबाइल रिचार्ज के लिए निर्धारित धनराशि देने की भी मांग उठाई गई। ज्ञापन में पंचायत, ब्लॉक, तहसील एवं जनपद स्तर पर कार्य के लिए आवागमन हेतु यात्रा भत्ता स्वीकृत करने, पंचायत सहायकों का मासिक वेतन निर्धारित तिथि तक समय से दिलाने तथा पंचायत भवनों पर कार्य हेतु रजिस्टर, कागज, प्रिंटर, इंक और फाइल जैसी आवश्यक कार्यालय सामग्री उपलब्ध कराने की मांग भी की गई।

इसके साथ ही पंचायत सहायकों ने यह भी आग्रह किया कि उनसे पंचायत कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य न लिए जाएं, ताकि उनके मूल दायित्व प्रभावित न हों। पंचायत सहायकों ने कहा कि यदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो पंचायत स्तर पर शासकीय कार्य अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुचारु रूप से संपन्न किए जा सकेंगे।

112 पुलिस की तत्परता से परिजनों से मिली गुमशुदा मासूम बच्ची

चार मिनट में मौके पर पहुंची पीआरवी टीम, परिजनों ने जताया आभार

गुन्नौर/सम्भल(सब का सपना):- जनपद में यूपी-112 पुलिस सेवा की तत्परता और सूझबूझ से एक गुमशुदा मासूम बच्ची को सकुशल उसके परिजनों से मिला दिया गया। घटना गुरुवार की है, जब थाना गुन्नौर क्षेत्र में संचालित यूपी-112 पीआरवी को कॉलर हरसित कुमार द्वारा सूचना दी गई कि महमूदपुर रोड पर एक अबोध बच्ची सड़क किनारे खड़ी जोर-जोर से रो रही है और अपने घर का रास्ता भूल गई है।

सूचना मिलते ही पीआरवी पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे। वहां करीब 3-4 वर्ष की एक बच्ची रोती हुई मिली। पुलिसकर्मियों ने बच्ची से उसका नाम और घर का

पता पूछने का प्रयास किया, लेकिन उम्र कम होने के कारण वह कुछ भी बताने में असमर्थ रही। इसके बाद पीआरवी कर्मियों ने थाना गुन्नौर को सूचना देते हुए बच्ची को अपने साथ लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ कर उसके परिजनों की तलाश शुरू की।

काफी प्रयास के बाद पुलिस टीम ने बच्ची के पिता शकील पुत्र अब्दुल मजीद निवासी मोहल्ला शेखान थाना गुन्नौर को तलाश कर बच्ची को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया। बच्ची को सुरक्षित पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली और यूपी-112 पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मानवीय कार्यशैली की सराहना की।

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एवं नोडल अधिकारी यूपी-112 मनोज कुमार रावत तथा प्रभारी निरीक्षक यूपी-112 रजनीश कुमार के निर्देशन में पीआरवी टीम ने मात्र चार मिनट में मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की।

अनाज मंडी बहजोई के नाले में मिले युवक के शव की हुई पहचान

सोशल मीडिया के जरिए भाई ने की पहचान, पुलिस जांच में जुटी

बहजोई/सम्भल(सब का सपना):- जनपद के कोतवाली बहजोई की अनाज मंडी स्थित नाले में गुरुवार सुबह मिले अज्ञात शव की पहचान शुक्रवार को हो गई। कोतवाली बहजोई पुलिस ने शव की पहचान वेदपाल पुत्र भूदेव निवासी खजरा खाकम थाना बहजोई जनपद सम्भल, उम्र करीब 32 वर्ष के रूप में कराई है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8 बजे अनाज मंडी बहजोई के नाले में पानी के अंदर एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाकर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन तत्काल पहचान नहीं

हो सकी। इसके बाद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर फोटो सहित संदेश वायरल कर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया।

शुक्रवार को मृतक के बड़े भाई हरिओम पुत्र भूदेव ने सोशल मीडिया पर फोटो देखकर शव की पहचान अपने छोटे भाई वेदपाल के रूप में की। इसके बाद वह थाने पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। कोतवाली बहजोई के क्राइम इंस्पेक्टर बलराम यादव ने बताया कि मृतक मानसिक रूप से बीमार था और शराब पीने का आदी भी था। परिजनों के अनुसार वेदपाल करीब एक सप्ताह पहले अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी के घर ग्राम पानीवाड़ा थाना रजपुरा गया था और 5 मई को वहां से वापस लौटा था। बबराला पहुंचकर उसने अपनी पत्नी बवली को फोन कर घर आने की बात कही थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि परिवार को किसी पर कोई शक नहीं है। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है तथा मृतक के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है।

धामपुर स्योहारा रोड पर सड़क हादसे में सफाई कर्मचारी की मौत

बिजनौर (सब का सपना):- धामपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। स्योहारा रोड पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

हादसा धामपुर थाना क्षेत्र के सरकड़ा चक्रराजमल के पास हुआ। जानकारी के अनुसार हसनपुर पालकी गांव निवासी मुनेश्वर सिंह पुत्र उमेश चंद्र अपनी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार

रोडवेज बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मुनेश्वर सिंह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बताया गया है कि 48 वर्षीय मुनेश्वर सिंह ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। उनके परिवार में पांच बच्चे हैं। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं टक्कर मारने वाली रोडवेज बस और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री ओमवती देवी का निधन, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर

बिजनौर (सब का सपना):- जनपद की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री, पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री ओमवती देवी का गुरुवार शाम निधन हो गया। वह रिटायर्ड प्रमुख सचिव आर.के. सिंह की पत्नी थीं। उनके निधन की खबर से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

उनके निधन की जानकारी उनकी पौत्रवधू एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैनरीता राजीव सिंह ने दी। बताया

गया कि गुरुवार शाम करीब चार बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

ओमवती देवी लंबे समय तक सक्रिय राजनीति और जनसेवा से जुड़ी रहीं। उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दें।

महिलाओं की श्रद्धा देख दो दिन बढ़ाया गया धार्मिक कार्यक्रम, भजन-कीर्तन में झूमीं श्रद्धालु

हयातनगर/सम्भल(सब का सपना):- जनपद के हयातनगर में चल रहे धार्मिक कार्यक्रम में महिलाओं की आस्था, भक्ति और श्रद्धा को देखते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं दीपा बाष्णेय ने आयोजन को दो दिन और आगे बढ़ाने की घोषणा की।

कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया, जबकि 9 मई की सुबह सुंदरकांड पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इस दौरान

बड़ी संख्या में महिलाओं ने कई घंटों तक भजन-कीर्तन एवं धार्मिक नृत्य कर भक्तिमय माहौल बना दिया।

पूरे आयोजन स्थल पर श्रद्धा और उत्साह का वातावरण देखने को मिला।

महिलाओं ने भगवान के भजनों पर झूमते हुए धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की। आयोजकों ने बताया कि श्रद्धालुओं के बढ़ते उत्साह और सहभागिता को देखते हुए कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

सांसद भोला सिंह ने किया सीसी रोड का लोकार्पण

बुलन्दशहर (सब का सपना):- जनपद के पहासू क्षेत्र के गांव सोही स्थित आदर्श किसान इंटर कॉलेज एवं कसूमी फजलपुर में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद भोला सिंह ने सीसी रोड का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर ग्रामीणों एवं इंटर कॉलेज प्रबंधन ने सड़क निर्माण को क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताते हुए सांसद का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने

से विद्यार्थियों और ग्रामवासियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन परवेंद्र देशवाल ने किया, जबकि अध्यक्षता सूबेदार रनवीर सिंह ने की। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह, ब्लॉक प्रमुख पति मुनेश कुमार, अहमदगढ़ मंडल अध्यक्ष रविंद्र मीणा, सांसद प्रतिनिधि मनोज गर्ग, श्रीराम सैनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रीतम सिंह, गोपाल शर्मा, संजय सूर्यवंशी, पद्म सिंह तौमर एवं विक्रांत सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

वर्तमान समय में सोशल मीडिया का प्रभाव एक वैज्ञानिक अध्ययन विषय पर अतिथि व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित

गुलावठी/बुलंदशहर (सब का सपना):- डी. एन. कॉलेज, गुलावटी के रसायन शास्त्र विभाग के तत्वावधान में वर्तमान समय में सोशल मीडिया का प्रभाव एक वैज्ञानिक अध्ययन विषय पर एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को सोशल मीडिया के वैज्ञानिक, सामाजिक एवं मानसिक प्रभावों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ महेंद्र कुमार ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान युग डिजिटल क्रांति का युग है, जिसमें सोशल मीडिया संचार का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया का सकारात्मक एवं रचनात्मक उपयोग करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विवेकपूर्ण सोच के साथ

तकनीक का उपयोग करना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ रोशन लाल रहे। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि सोशल मीडिया आज के समाज को गहराई से प्रभावित कर रहा है। इसके माध्यम से ज्ञान, सूचना एवं जागरूकता का तीव्र प्रसार संभव हुआ है, वहीं इसके अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग से मानसिक तनाव, समय की बबार्दी तथा सामाजिक संबंधों में दूरी जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों एवं उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के संतुलित उपयोग के लिए प्रेरित किया। रसायन शास्त्र विभाग प्रभारी डॉ विनीता गर्ग ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस प्रकार के व्याख्यान विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास एवं वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। कार्यक्रम में हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ हरीश कसाना अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग ज्ञानवर्धन, साहित्य, संस्कृति एवं सकारात्मक संवाद के लिए किया जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों को इसकी उपयोगिता एवं दुष्प्रभावों के प्रति सजग रहना चाहिए।

कार्यक्रम में भौतिक विज्ञान विभाग से नरेश कुमार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ विनय कुमार सिंह ने किया।

कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। अंत में सभी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक बताया।

एसएसपी ने साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर पुलिसकर्मियों का किया निरीक्षण

बुलन्दशहर (सब का सपना):- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर पुलिसकर्मियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के टर्नआउट, शस्त्र संचालन तथा आपदा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

एसएसपी ने पीआरवी/डायल-112 वाहनों की भी जांच की और उनमें उपलब्ध मेडिकल किट, येलो टेप सहित अन्य आवश्यक उपकरणों की

स्थिति परखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रिस्पांस टाइम बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए।

इसके उपरांत एसएसपी ने आदेश कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। वहीं पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण करते हुए स्वच्छता व्यवस्था, सरकारी संपत्ति के रखरखाव तथा वाहनों की नियमित मेंटेनेंस सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर प्रखर पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को किया जागरूक

बुलन्दशहर (सब का सपना):- मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति टीमों द्वारा मंदिरों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं

एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान महिला सुरक्षा, साइबर अपराध रोकथाम, गुड टच-बैड टच, आत्मरक्षा एवं विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।

शिकारपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने की स्वगणना, नागरिकों से सहभागिता की अपील

बुलन्दशहर (सब का सपना):- जनपद के शिकारपुर में भारत सरकार के स्वगणना अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद अध्यक्ष राजबाला देवी ने स्वयं स्वगणना कर नगरवासियों को अभियान में भागीदारी का संदेश दिया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह भी उपस्थित रहीं।

अध्यक्ष राजबाला देवी ने कहा कि जनगणना देश के विकास और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने

नागरिकों से समय रहते स्वगणना पूर्ण करने और अन्य लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह ने बताया कि 7 मई से 21 मई 2026 तक चल रहे स्वगणना अभियान के तहत नगर पालिका द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नागरिक भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in पर घर बैठे ऑनलाइन स्वगणना कर सकते हैं। साथ ही स्वगणना के बाद प्राप्त आईडी को सुरक्षित रखने की भी अपील की गई, ताकि 22 मई से 20 जून के बीच घर आने वाले प्रगणक को यह आईडी दिखाई जा सके।

डिबाई पुलिस ने साइबर ठगी के 13,740 रुपये पीड़ित के खाते में कराए वापस

डिबाई/बुलन्दशहर (सब का सपना):- थाना डिबाई पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार हुए व्यक्ति की रकम वापस कराकर सराहनीय कार्य किया है। ग्राम रहमापुर निवासी विजय सिंह के बैंक खाते से अज्ञात साइबर ठगों द्वारा 13,740 रुपये निकाल लिये गए थे। शिकायत मिलने पर थाना डिबाई साइबर हेल्प डेस्क ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अथक

प्रयासों से पूरी धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में की गई कार्रवाई पर पीड़ित ने डिबाई पुलिस का आभार जताया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से ओटीपी, पिन, सीवीवी या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें तथा साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क।

बाढ़ तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट, गंगा घाटों पर नाव संचालन के लिए जारी किए सख्त निर्देश

बुलन्दशहर (सब का सपना):- जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) अभिषेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों को अपनी बाढ़ कार्ययोजना शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए।

गंगा घाटों पर संभावित हादसों को देखते हुए नाव व स्टीमर संचालन के लिए प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी नावों का

पंजीकरण, फिटनेस टेस्ट, नाविकों का पुलिस सत्यापन और बोट मैनेजमेंट पोर्टल पर विवरण दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, सूर्यास्त के बाद संचालन तथा बिना लाइफ जैकेट यात्रा पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी नावों में लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, रस्सी, टॉर्च और प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। प्रशासन ने खराब मौसम में नाव संचालन पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

मेरठ रेंज IGRS में अव्वल, चारों जनपदों ने हासिल किया प्रथम स्थान

बुलन्दशहर (सब का सपना):- मेरठ परिक्षेत्र ने IGRS पोर्टल पर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण में अप्रैल 2026 की रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रेंज के मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ जनपद भी प्रथम स्थान पर रहे।

कलानिधि नैथानी ने बताया कि शासन की मंशानुसार शिकायतों का त्वरित व विधिक निस्तारण कराया गया। डीआईजी ने सभी जनपदों की सराहना करते हुए शिकायतों के निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश।

स्कूल में पढ़ाई की जगह डर का माहौल, बच्चों ने खोली पोल

सर हमें मारते हैं, बच्चों की शिकायत लेकर बीएसए दफ्तर पहुंचे छात्र

बिजनौर (सब का सपना):- नहटौर ब्लॉक क्षेत्र के मीमला जमालपुर स्थित कम्पोजिट विद्यालय के दर्जनों स्कूली बच्चों ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिक्षक के खिलाफ प्रदर्शन किया। बच्चों ने शिक्षक पर मारपीट, गाली-गलौज और बदसलूकी के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे बच्चों का आरोप है कि विद्यालय में तैनात शिक्षक सौरभ उनके साथ मारपीट करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों का कहना है कि शिक्षक के व्यवहार से वे भयभीत हैं और पिछले करीब एक महीने से कई छात्र-छात्राएं स्कूल जाने से डर रहे हैं। बच्चों ने बताया कि इससे पहले भी मामले को लेकर शिकायत और ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि आरोपी शिक्षक

को विद्यालय से हटाया जाए ताकि छात्र सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सकें। प्रदर्शन में शामिल छात्राओं नंदिनी, आयशा और इकरा समेत कई बच्चों ने आरोप लगाया कि शिक्षक उन्हें गंदी गालियां देते हैं और छोटी-छोटी बातों पर पीटते हैं। इसी शिकायत को लेकर वे बीएसए कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से न्याय की मांग की। ग्राम प्रधान अशोक कुमार ने भी बच्चों के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षक का व्यवहार लंबे समय से विवादों में है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत करने पहुंचे अभिभावकों के साथ भी शिक्षक अभद्रता करते हैं।

वहीं किसान यूनियन नेता मुनेश कुमार ने कहा कि शिक्षक के खिलाफ पहले भी शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई न होने से बच्चों और ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर सख्त कदम उठाने की मांग की।

सावधान: स्योहारा-नूरपुर रोड का रेलवे फाटक 5 दिनों के लिए बंद

स्योहारा/बिजनौर (सब का सपना):- यदि आप स्योहारा-नूरपुर मार्ग से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। रेलवे ट्रैक की मरम्मत के चलते स्योहारा-नूरपुर मुख्य मार्ग का रेलवे फाटक 7 मई से 11 मई तक पूरी तरह बंद रहेगा। आपको बता दे कि स्योहारा और चकराजमल स्टेशन के बीच स्थित रेलवे फाटक संख्या 446/बी (किलोमीटर 1445/04-06) की हालत काफी जर्जर हो चुकी थी। रेल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग यहाँ खराब स्लीपर और रेल लाइन बदलने का बड़ा मरम्मत कार्य कर रहा है। जिसकी अवधि 7 मई प्रातः 6:00 बजे से 11 मई सायं 6:00 बजे तक रहेगी। अगर आपको किसी जरूरी कार्य से जाना भी है तो आपको दूसरा रास्ता शुगर मिल के पास स्थित रेलवे फाटक संख्या 445/बी (दूरी लगभग 3 किमी अतिरिक्त), ईदगाह विरामपुर रेलवे फाटक संख्या 447/सी (दूरी लगभग 4 किमी अतिरिक्त) से आप

जा सकते हैं।सामान्य दिनों में जो दूरी मात्र 300 मीटर की थी, अब फाटक बंद होने के कारण यात्रियों को 3 से 4 किलोमीटर का चक्कर काटकर जाना होगा। विशेषकर स्कूली वाहनों, एम्बुलेंस और व्यापारिक माल ढोने वाले वाहनों के लिए यह पांच दिन काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं।

रेलवे विभाग ने जनता से धैर्य रखने और सहयोग की अपील की है। जाम और परेशानी से बचने के लिए घर से थोड़ा समय लेकर निकलें और निर्धारित डायवर्जन का ही पालन करें।

गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध से पहले व्यापारी नेता हाउस अरेस्ट

बिजनौर (सब का सपना):- बढ़ती महंगाई और कमर्शियल गैस सिलेंडरों के बढ़े दामों के विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले शुक्रवार सुबह व्यापारी नेता राहुल वर्मा को प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। व्यापारी एकता परिषद के बैनर तले जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की तैयारी की गई थी। जानकारी के अनुसार व्यापारी एकता परिषद ने शुक्रवार को बढ़ते कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों के विरोध में प्रदर्शन और ज्ञापन देने का आह्वान किया था। इसी बीच सुबह जिला प्रशासन ने व्यापारी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राहुल वर्मा को उनके आवास पर ही रोक दिया, जिसके बाद व्यापारियों में नाराजगी फैल गई। राहुल वर्मा ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ रही महंगाई और गैस सिलेंडरों की कीमतों ने छोटे व्यापारियों, होटल संचालकों, ढाबा मालिकों, मिठाई व्यापारियों और रेस्टोरेंट कारोबारियों की

आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी पहले से ही स्मार्ट मीटर, बढ़ते टैक्स और आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, ऐसे में कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम व्यापार को चौपट करने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार यह सोचती है कि व्यापारियों को दबाकर आंदोलन रोका जा सकता है तो यह उसकी भूल है। व्यापारी वर्ग अन्याय, शोषण और महंगाई के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहेगा।

व्यापारी एकता परिषद ने चेतावनी दी कि यदि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और इस प्रकार की कार्रवाई बंद नहीं हुई तो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

इस घटनाक्रम के बाद व्यापारियों में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है।

पानीपत में मंदिर की दीवार फांदकर घुसे चोर, मूर्तियां खंडित कर ले गए पीतल के घंटे;सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पानीपत। मनमोहन नगर स्थित एक मंदिर में बुधवार मध्यरात्रि चोरी और तोड़फोड़ की गई। चोर मंदिर का दानपात्र तोड़ नकदी, पीतल के घंटे और भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा चोरी कर ले गए। वहीं, मंदिर में स्थापित हनुमानजी की मूर्ति को भी खंडित कर दिया। घटना के बाद कॉलोनीवासियों और बजरंग दल कार्यकताओं में भारी रोष है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनमोहन नगर निवासी दीपक वर्मा ने बताया कि कॉलोनी में स्थित मंदिर में बुधवार रात करीब दो बजे चोर घुस आए। सुबह जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो दानपात्र टूटा मिला। मंदिर से पीतल के घंटे और भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा नहीं थी। इसके अलावा हनुमानजी की मूर्ति भी खंडित मिली। मंदिर की हालत देखकर लोगों में आक्रोश फैल गया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद थाना किला पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाश मंदिर के पीछे की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भी विक्की के नेतृत्व में मंदिर पहुंचे।कार्यकताओं ने धार्मिक स्थल में चोरी और मूर्ति खंडित करने की घटना पर कड़ा विरोध जताया। विक्की ने बताया कि मंदिर में लगे सीसीटीवी में आरोपित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैमरे दूर होने के कारण उनकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत, 6 महीने में नियमितीकरण पर आएगा नया फैसला; नहीं जाएगी किसी की नौकरी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार, उसके बोर्डों, निगमों और विभिन्न विभागों में वर्षों से नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हजारों कच्चे, अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने 98 अपीलों के संयुक्त निपटारे में स्पष्ट कर दिया कि कर्मचारियों के नियमितीकरण के दावों पर अब पुरानी नीतियों की सामान्य व्याख्या की बजाय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 अप्रैल 2026 को दिए गए ह्यमदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य निर्णय के आधार पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार, बिजली निगमों, नगर निगमों, हाउसिंग बोर्ड और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक कर्मचारी के मामले की व्यक्तिगत जांच कर छह माह के भीतर कारण युक्त यानी स्पीकिंग आर्डर पारित करें। मौजूदा सेवा स्थिति में कोई प्रतिकूल बदलाव नहीं अदालत ने यह भी साफ किया कि जब तक संबंधित कर्मचारी के दावे पर अंतिम प्रशासनिक निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उसकी मौजूदा सेवा स्थिति में कोई प्रतिकूल बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी फिलहाल कर्मचारियों को कार्यरत स्थिति से हटाने या नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई पर रोक जैसी सुरक्षा मिल गई है। खंडपीठ ने इससे पहले सिंगल बेंच द्वारा 22 जनवरी 2025 को दिए गए आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि अब 1996, 2003, 2011, 2014 अथवा 2024 की नीतियों पर विचार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय संवैधानिक सिद्धांतों के अधीन होगा।अदालत ने माना कि ह्यउमा देवी फैसले और उसके बाद योगेश त्यागी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की अंतिम व्याख्या के बाद राज्य को प्रत्येक कर्मचारी के सेवा रिकार्ड, पात्रता और नीति की वैधता के अनुसार निर्णय लेना होगा। लंबित नियमितीकरण विवादों के समाधान का नया ढांचा तैयार हरियाणा सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि सभी कर्मचारियों के दावों की नये सिरे से जांच की जाएगी, जिसके बाद कोर्ट ने व्यापक बहस में जाने की बजाय पूरी प्रक्रिया को प्रशासनिक पुनर्विचार के लिए भेज दिया। साथ ही प्रत्येक कर्मचारी को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के दो सप्ताह के भीतर अपने विभाग को विस्तृत अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे हरियाणा के विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित नियमितीकरण विवादों के समाधान का नया ढांचा तैयार हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए थे।

टीबी मुक्त हरियाणा अभियान तेज, 30 दिन में 10 हजार से ज्यादा नए मरीजों की पहचान; एआई तकनीक ने बढ़ाई रफ्तार

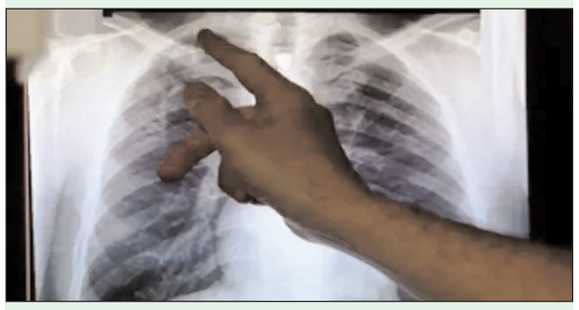

चंडीगढ़। हरियाणा में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस पर शुरू हुए 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान (फेज-2) की 30 दिन की रिपोर्ट जारी की गई है। अभी तक 10 हजार 978 नए टीबी मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इस दौरान कुल एक लाख 81 हजार 221 लोगों की स्क्रीनिंग की गई और करीब 50 हजार न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (एनएएटी) किए गए। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने शुक्रवार को बताया कि कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) आधारित तकनीकों और सक्रिय केस खोज रणनीति से नए मरीजों को ढूंढ़ा जा रहा है। ह्यटीबी मुक्त हरियाणा के लक्ष्य के तहत व्यापक जन-जागरूकता अभियान, आधुनिक तकनीक और सामुदायिक भागीदारी के चलते टीबी उन्मूलन को नई गति मिली है। राज्य की रणनीति केवल मरीजों के सामने आने का इंतजार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जाकर लक्षण रहित लोगों की भी जांच की जा रही है, ताकि छिपे हुए मामलों की समय रहते पहचान हो सके। एआई-सक्षम हाथ से संचालित एक्स-रे मशीनें' दूरदराज क्षेत्रों में तुरंत जांच की सुविधा दे रही हैं। कफ अगेंस्ट टीबी एप खांसी की आवाज का विश्लेषण कर संभावित मरीजों की पहचान करने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. आरएस ढिल्लों ने बताया कि 65 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को ह्यचलती-फिरती लैबह्ल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी जांच संभव हो पाई है। जनप्रतिनिधियों और पंचायत संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से टीबी से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने में मदद मिली है। टीबी जांच को सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ जोड़ा गया है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और एनीमिया की जांच भी शामिल है, ताकि समग्र स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।उन्होंने बताया कि जियोस्पेशियल तकनीक के माध्यम से 2111 संवेदनशील गांवों और वार्डों की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एक महीने में कुल 1620 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें से 938 उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लगाए गए। इस अवधि में 335 नए निक्षय मित्र पंजीकृत किए गए, जबकि 8502 पोषण किट वितरित की गई हैं।

युपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में बने 89 परीक्षा केंद्र, 24 मई को होगा प्रीलिम्स

चंडीगढ़। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में केंद्र बनाए गए हैं। 24 मई को फरीदाबाद में 37 और गुरुग्राम में 52 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को गुरुग्राम और फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त, उपायुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में कहा कि नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित करें। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं, कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर रखा जाए। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, निर्बाध बिजली आपूर्ति, सुगम परिवहन सुविधाएं और प्रभावी भीड़ प्रबंधन के लिए समय रहते सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी सतर्कता, ईमानदारी और पेशेवर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

हरियाणा में अवैध खनन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी माइनिंग साइट्स की हर साल होगी ड्रोन मैपिंग

चंडीगढ़। हरियाणा में कथित अवैध खनन पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश की सभी खनन साइट्स की अनिवार्य रूप से हर वर्ष ड्रोन मैपिंग करवाई जाए, ताकि अवैध खनन की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल तकनीक सर्वेक्षण और वैज्ञानिक रिकॉर्डिंग के जरिए ही खनन नियमों के उल्लंघन को सही ढंग से पकड़ा और रोका जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे में यह मांग की गई थी कि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने और पर्यावरणीय नुकसान का आकलन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की अनुमति दी जाए। लेकिन जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।खंडपीठ ने कहा कि मामला अत्यधिक तकनीकी प्रकृति का है और अवैध खनन की सीमा, पर्यावरणीय प्रभाव तथा वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। अदालत ने साफ कहा कि सेवानिवृत्त जज के पास जरूरी तकनीकी दक्षता होना आवश्यक नहीं, इसलिए इस प्रकार की जांच उनके नेतृत्व में कराना उचित नहीं माना जा सकता।हाई कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह तुरंत आवश्यक आदेश जारी कर राज्य की सभी खनन साइट्स की वार्षिक ड्रोन मैपिंग सुनिश्चित करें। अदालत ने यह भी कहा कि हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए पूरे राज्य के खनन क्षेत्रों का वैज्ञानिक डेटा जुटा सकता है।सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि राज्य सरकार की चिंता उचित है, लेकिन अवैध खनन की जांच का सबसे प्रभावी तरीका तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक परीक्षण ही है। यह मामला चरखी दादरी जिले के पिचोपा कलां गांव में कथित अंधाधुंध अवैध खनन से जुड़ा है, जहां याचिकाकताओं ने आरोप लगाया कि स्वीकृत सीमा से कहीं अधिक खनन कर कृषि भूमि, पर्यावरण और गांव की पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया।

'हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध चिंताजनक...', कुमारी सैलजा ने नायब सरकार पर बोला हमला

सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार हरियाणा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, वह बेहद गंभीर स्थिति है। कुमारी सैलजा ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामलों में हरियाणा देश में सबसे आगे है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। यह स्थिति हरियाणा जैसे प्रगतिशील प्रदेश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा को विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में देश के लिए उदाहरण बनना चाहिए था, लेकिन आज प्रदेश अपराध, भय और असुरक्षा की घटनाओं के कारण चर्चा में है। सांसद सैलजा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त और ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही नशे के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
उन्होंने कहा कि केवल दावे और प्रचार से स्थिति नहीं सुधरेगी, सरकार को जमीन पर परिणाम देने होंगे। सांसद ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार देश में 2024 में लड़कियों की तस्करी के 1659 केस हुए इनमें सबसे ज्यादा हरियाणा में दर्ज हुए। लोकसेवकों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है। अवैध हथियारों के मामले में हरियाणा देश में पांचवें स्थान पर है।

भिवानी में खुले बिजली बॉक्स से बड़ा खतरा, कभी भी हो सकता है जानलेवा हादसा

भिवानी। शहर में लगे ज्यादातर पिल्लर बॉक्स खुले पड़े हैं। इन पर किसी प्रकार का लॉक तक नहीं है। आस पास के लोग जब मन आए अपने तार बदलते रहते हैं। इसके लिए कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। जब ये पिल्लर बॉक्स लगे थे उस समय भी लोगों ने बहुत विरोध किया था। इनकी सुरक्षा पर सवाल उठाए थे लेकिन अब बिजली निगम ही इस मामले को लेकर लापरवाह बना है। इसके लिए खुद बिजली कर्मचारी और अधिकारी भी जिम्मेदार हैं।हालांकि, इन पर ताला लगाने के बाद उस इलाके लाइनमैन के पास चाबी रहनी चाहिए और बाहर का कोई खोल न सके इसके लिए जरूरी प्रबंध किए जाने चाहिए पर ऐसा वर्षों से नहीं किया जा रहा है। बिजली निगम इस मामले में कब जागेगा यह निगम जाने या फिर ऊपर वाला जाने। लगता है निगम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है।जैन चौक केएम स्कूल के सामने बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां सड़क किनारे लगे इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स खुले पड़े हुए हैं, जिनसे आमजन की सुरक्षा को बड़ा खतरा बना हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता वं सैनी विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश सैनी ने इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि विभाग की अनदेखी के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सुरेश सैनी ने कहा कि जिस स्थान पर बिजली के मीटर बॉक्स खुले पड़े हैं, वहां से प्रतिदिन सैकड़ों स्कूली बच्चे, अभिभावक, महिलाएं और राहगीर गुजरते हैं। बच्चों में जागरूकता की कमी होने के कारण वे अनजाने में इन बॉक्स के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे करंट लगने जैसी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा आसपास आवारा पशु भी घूमते रहते हैं, जिनके लिए भी यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि कई बार स्थानीय लोगों द्वारा इस समस्या की ओर ध्यान दिलाने के बावजूद अभी तक बिजली विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। खुले तार और खुले मीटर बॉक्स प्रशासनिक लापरवाही को दशार्ते हैं। बरसात या नमी के मौसम में यह खतरा और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ी सी चूक किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। सुरेश सैनी ने कहा कि शहर में बच्चों की सुरक्षा और आमजन की सुविधा को लेकर विभाग को गंभीरता दिखानी चाहिए। स्कूलों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बिजली उपकरणों की नियमित जांच आवश्यक है ताकि हादसों से बचा जा सके। उन्होंने मांग की कि बिजली विभाग तुरंत प्रभाव से खुले पड़े मीटर बॉक्स को सुरक्षित तरीके से बंद करवाए तथा आसपास सुरक्षा चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएं। उन्होंने प्रशासन से भी अपील की कि ऐसे संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोबारा देखने को न मिले। सुरेश सैनी ने कहा कि जन सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है और समय रहते समाधान करना ही प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होंगी

2100 रुपये फिर भेजे गए अकाउंट में... हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी; किसानों को भी मिला मुआवजा

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार (08 मई, 2026) को चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष राज्य स्तरीय कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से करोड़ों रुपये की लाभ राशि वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और फसल मुआवजा समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित भी किया। लाडो लक्ष्मी योजना की सातवीं किस्त जारी मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना की सातवीं किस्त आज जारी कर दी गई है। उन्होंने 9 लाख 76 हजार लाभार्थी बहनों के खाते में कुल 205 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा, गैस सिलेंडर सब्सिडी के रूप में 11 लाख 23 हजार बहनों के खातों में 38 करोड़ 54 लाख रुपये भी भेजे गए।वहीं, अन्नदाताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने खरीफ 2025 की फसल नुकसान के लिए 1,50,583 किसानों को 370 करोड़ 52 लाख रुपये की मुआवजा राशि वितरित की। जे-फॉर्म अब वॉट्सऐप पर सीएम नायब सैनी ने इस दौरान एक नई ऐप की शुरूआत की, जिससे अब किसानों को अपनी फसल का जे-फॉर्म लेने के लिए आढ़तियों के पास नहीं जाना होगा। यह फॉर्म सीधे उनके वॉट्सऐप पर आएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 82 लाख 55 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है और किसानों को 16,481 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देते हुए मुख्यमंत्री ने 18 विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 62 हजार लाभार्थियों के खातों में 1146 करोड़ 73 लाख रुपये की राशि डाली। वहीं, अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (BC) के 64,923 विद्यार्थियों को 100 करोड़ 45 लाख रुपये की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया।

बहादुरगढ़: पार्क में खून से लथपथ मिली युवती की लाश, 'युवक ने प्रेमिका की गर्दन काटकर खुद पर किया जानलेवा वार'

बहादुरगढ़। हरियाणा के बहादुरगढ़ में देवीलाल पार्क में युवक-युवती लहूलुहान हालात में मिले। युवती का गला रेता हुआ था, जबकि युवक गंभीर हालत में था। आशंका है कि युवक ने युवती का गला काटने के बाद खुद का गला रेता होगा। बताया गया कि युवक का बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीसीपी मयंक मिश्रा मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की जांच में पता चला कि जनवरी में दोनों की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। अभिषेक बिजली-पलंबर का काम करता है।दोनों की पहचान हो गई है। युवक अभिषेक निवासी सैमाण, टोहाना फतेहाबाद है, जबकि युवती बिहार की रहने वाली थी। युवती का परिवार बहादुरगढ़ के शक्ति नगर में रहता है। युवक का कहना है कि युवती ने फोन कर बुलाया था। बताया कि पीछे से दो युवक आए और हमला कर दिया। मगर यह कहानी पुलिस को हजम नहीं हो रही है। क्योंकि युवक की हाथ की नस भी कटी है।

फरीदाबाद: 13 लाख की लूट निकली झूठी कहानी, कर्मचारी पर गबन का मुकदमा दर्ज; मोटी रकम बरामद

फरीदाबाद। दिल्ली से फरीदाबाद 13 लाख रुपये लेकर आए कर्मचारी द्वारा लूट की बताई गई वारदात पुलिस जांच में झूठी निकली है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच में कहानी की पुष्टि नहीं होने पर पुलिस ने कर्मचारी के खिलाफ गबन और साजिश रचने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कारोबारी ने दी शिकायत दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन निवासी कारोबारी शैलेश राम राय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी राय इनोटेक पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है। कंपनी में पिछले करीब 10 वर्षों से नवल किशोर फील्ड वर्कर के तौर पर काम कर रहा है। शिकायत के अनुसार, शाम करीब पांच बजे उन्होंने नवल किशोर को 13 लाख रुपये सेक्टर-10 स्थित कारोबारी राठी को देने के लिए दिए थे। नवल किशोर रुपये बैग में रखकर स्कूटी पर दिल्ली से फरीदाबाद के लिए निकला था। चाकू दिखाकर बैग छीन लिया शिकायतकर्ता के अनुसार, शाम करीब 7:15 बजे नवल किशोर ने फोन कर बताया कि बाटा चौक फ्लाईओवर के पास बाइक सवार दो युवकों ने चाकू दिखाकर उसका बैग छीन लिया। आरोप था कि बैग में 13

लाख रुपये थे और आरोपित हेलमेट पहने हुए थे, इसलिए वह उनकी पहचान नहीं कर सका।मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवल किशोर से पूछताछ की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और तकनीकी पहलुओं की जांच की, लेकिन कथित लूट की कहानी की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद

फरीदाबाद में 13 लाख रुपये की लूट की बताई गई घटना पुलिस जांच में झूठी निकली। कर्मचारी नवल किशोर ने गबन के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर 12.5 लाख रुपये बरामद किए।

कारोबारी शैलेश राम राय ने थाना पहुंचकर शिकायत दी और आरोप लगाया कि नवल किशोर ने अपने साथियों के साथ मिलकर रकम के गबन के लिए झूठी कहानी रची है।
साढ़े 12 लाख रुपये बरामद
पुलिस ने शिकायत और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नवल किशोर और उसके साथियों के खिलाफ गबन, झूठी सूचना देने और साजिश रचने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अभी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस मामले में नवल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे साढ़े 12 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं।

खबर एक्सप्रेस

पंजाबः जालंधर डीसी ने पांच जूनियर असिस्टेंट को दी सीनियर पोस्ट, लिस्ट में ये नाम शामिल

जालंधर। डीसी वरजीत वालिया ने वरिष्ठ सहायक के रिक्त पदों को भरने के लिए वीरवार को पांच कनिष्ठ सहायकों को पदोन्त कर वरिष्ठ सहायक बना दिया है। पदोन्नत होने वालों में सुरजीत सिंह, कनिष्ठ सहायक, उपतहसील कार्यालय, लोहियां, मुनीश शर्मा, कनिष्ठ सहायक, उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय, आदमपुर, परमिंदर सिंह, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार, नकोदर, सुखजीत सिंह, कनिष्ठ सहायक, उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय, फिल्लौर तथा मुनीश सैनी, कनिष्ठ सहायक, विकास शाखा, उपायुक्त कार्यालय, जालंधर का नाम शामिल है। ये कर्मचारी वरिष्ठ सहायक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान इन कर्मचारियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उन्हें उनके मूल पद पर पुनः नियुक्त कर दिया जाएगा।वहीं, दो दिन पहले पंजाब सरकार ने प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से राज्य के पुलिस विभाग में महत्वपूर्ण फेरबदल किया है। गृह विभाग (Home-I Branch)) द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और पंजाब पुलिस सेवा (PPS) के 6 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं।

शुक्राना यात्रा का आखिरी दिन, बठिंडा पहुंचे सीएम मान; भाजपा पर हमला, भाईचारा बिगाड़ने का लगाया आरोप

बठिंडा। जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कानून बनने के बाद निकाली जा रही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की शुकराना यात्रा गुरुवार को बठिंडा पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख संगतों और आम लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। जगह-जगह फूल बरसाए गए और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमेशा भाईचारे, शांति और आपसी सद्भाव की धरती रहा है और यहां के लोगों को ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है जो लोगों को बांटने की राजनीति करती हैं।भाजपा के सत्ता में आने के बाद हालात बिगड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देकर लोगों के बीच दूरी पैदा की जा रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को राजनीतिक हमला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह आज बठिंडा में अकाल पुरख का शुक्राना करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि परमात्मा की कृपा और लोगों के समर्थन से उनकी सरकार जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कानून बनाने में सफल रही। मुख्यमंत्री ने इसे पंजाब की धार्मिक भावनाओं और सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया।बेअदबी की घटनाओं पर सख्त सरकार उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हमेशा पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की रक्षा के लिए काम करती रहेगी। लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है ताकि भविष्य में बेअदबी जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। यात्रा मार्ग पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। शुक्राना यात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकताओं में भी भारी उत्साह दिखाई दिया। कार्यकताओं ने मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाए और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री के बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ सरकार इसे सामाजिक एकता और धार्मिक सम्मान से जोड़कर पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री की शुक्राना यात्रा पंजाब के विभिन्न जिलों में जारी है।

पंजाब की हाई सिक्योरिटी जेल में चूक, सिस्टम भी हुआ फेल; यहां रक्षक ही पकड़े गए तस्करी करते

बठिंडा। पंजाब की हाई सिक्योरिटी बठिंडा की केंद्रीय जेल में लगातार सामने आ रहे नशा तस्करी के मामलों ने जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल के दिनों में जेल के भीतर से अफीम, हेरोइन, जर्दा और अन्य प्रतिबंधित सामान की बरामदगी ने यह साफ कर दिया है कि जेल के अंदर सक्रिय नेटवर्क अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। ताजा मामले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सिपाही राजिंदर सिंह को तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया। उसके पास से करीब 23.99 ग्राम अफीम, 158 ग्राम जर्दा और सिरिंज बरामद की गई। शुरूआती जांच में सामने आया कि यह सामान जेल के भीतर बंद कैदियों तक पहुंचाया जाना था। पूछताछ के दौरान आरोपित ने स्वीकार किया कि वह पैसों के लालच में यह काम कर रहा था। बीते सप्ताह भी पकड़ा गया था सीनियर कांस्टेबल जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ ही सप्ताह पहले जेल प्रशासन ने सीनियर कांस्टेबल अंग्रेज सिंह को भी गिरफ्तार किया था। आरोप था कि वह अपनी पगड़ी में 34 ग्राम हेरोइन छिपाकर जेल के भीतर ले जाने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह अ- कैटेगरी के गैंगस्टर सागर उर्फ मछली को नशा सप्लाई करता था और एक खेप पहुंचाने के बदले उसे करीब 20 हजार रुपये मिलते थे।पुलिस जांच में सामने आया कि अंगेज सिंह जिस गैंगस्टर को नशा पहुंचा रहा था, वह हत्या, लूट और संगठित अपराध के 50 से अधिक मामलों में आरोपित है। जांच एजेंसियों का मानना है कि जेल के भीतर बंद कई गैंगस्टर केवल नशे का सेवन ही नहीं करते, बल्कि अंदर से अपना नेटवर्क भी संचालित करने की कोशिश करते हैं।हर साल पकड़े जा रहे तस्करी में लिप्त कर्मचारी पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो 2019 में जेल गार्ड और पेस्को कर्मचारियों से नशीली गोलियां और मोबाइल फोन बरामद हुए थे। 2020 में एक पैरा लीगल वालंटियर कैदी तक मोबाइल फोन और जर्दा पहुंचाते पकड़ा गया। 2022 में एक जेल वार्डर को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि 2024 और 2025 में भी हेड वार्डर, एसआई और अन्य कर्मचारियों से नशा बरामद होने के मामले सामने आए। सवाल यह है कि यदि इतने वर्षों से लगातार घटनाएं सामने आ रही थीं, तो सुरक्षा व्यवस्था में ठोस सुधार क्यों नहीं किए गए। इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू जेल के भीतर सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हाई सुरक्षा जेल में भी लगातार नशा पहुंच रहा है तो यह केवल कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता नहीं बल्कि सुरक्षा प्रणाली की गंभीर विफलता को दशार्ता है। उनका मानना है कि जेलों में अकआधारित निगरानी प्रणाली, उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे, शरीर जांच यंत्र और डिजिटल गतिविधि निगरानी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

लुधियाना में स्नैचरों पर लोगों का फूटा गुस्सा, चार आरोपितों को कपड़े उतार पीटा; पुलिस ने हिरासत में लिया

लुधियाना। लुधियाना शहर में लगातार बढ़ रही लूटपाट और स्नैचिंग की घटनाओं के बीच बुधवार रात लोगों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब स्थानीय निवासियों ने चार आरोपितों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मामला गिल गांव से दुगरी जाने वाले रास्ते का है, जहां ओवरब्रिज के नीचे वारदात को अंजाम देने पहुंचे आरोपितों को लोगों ने घेरकर काबू कर लिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उनके कपड़े उतरवा जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार इलाके में लंबे समय से लूटपाट और स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही थीं। आरोपित राह चलते लोगों को रोककर तेजधार हथियारों के बल पर उनसे मोबाइल, नकदी और अन्य सामान छीनते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनकी गतिविधियों के कारण इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था।आरोपियों से तेजधार हथियार बरामद पकड़े गए आरोपितों की पहचान लक्की, सन्नी, मोनू और मनीष के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की दो मोटरसाइकिलें, तेजधार हथियार और लोहे की रॉड बरामद की है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दोनों मोटरसाइकिलों पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थीं।स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपित मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वारदात करते थे और सुनसान

इलाकों में लोगों को निशाना बनाते थे। बुधवार रात भी उन्होंने कुछ लोगों को घेरने की कोशिश की, लेकिन इस बार लोग सतर्क हो गए और आरोपितों को पकड़ लिया। एक युवक, जो खाने की वस्तुओं की घर-घर डिलीवरी करने का काम करता है, ने बताया कि आरोपितों ने उस पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उसकी टांग में चोट लगी। वहीं एक अन्य युवक की बाजू पर भी चोट आई है। हालांकि लोगों के विरोध के कारण आरोपित अपनी वारदात को पूरी तरह अंजाम नहीं दे सके।पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में लिया घटना की सूचना मिलने के बाद थाना दुगरी पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपितों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपितों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे पहले किन-किन वारदातों में शामिल रहे हैं।

साथ ही चोरी की बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

इलाके के लोगों ने कहा कि लगातार बढ़ती वारदातों के कारण लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो अपराधियों के हौसले और बढ़ सकते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपितों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है।

भाजपा में शामिल राज्यसभा सांसद की याचिका पर हाई कोर्ट सख्त, पूछा- एफआईआर है तो छिपा क्यों रही सरकार?

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पंजाब के एक राज्यसभा सांसद की याचिका पर शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में तीखी सुनवाई हुई। अदालत ने पंजाब सरकार से सख्त सवाल करते हुए पूछा कि यदि सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य छुपन-छुपाई की नीति नहीं अपना सकता। मामले की सुनवाई के दौरान सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 24 अप्रैल को पार्टी बदलने के बाद 2 और 3 मई को कई समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुईं कि पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की हैं। हालांकि अब तक न तो एफआईआर नंबर बताए गए हैं, न संबंधित थाना और न ही धाराओं की

जानकारी दी गई है। याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत से कहा कि सांसद केवल इतना जानना चाहते हैं कि यदि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है तो उसकी प्रति उपलब्ध करवाई जाए ताकि वह कानून के तहत अपना बचाव कर सकें।डीजीपी कार्यालय से भी नहीं मिला स्पष्ट जवाब

अदालत को यह भी बताया गया कि इस संबंध में पंजाब डीजीपी को लिखित प्रतिनिधित्व देकर जानकारी मांगी गई थी, लेकिन वहां से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि यदि कोई मामला दर्ज है तो उसकी जानकारी देना राज्य की जिम्मेदारी है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से यह भी आग्रह किया गया कि जब तक सरकार स्पष्ट स्थिति नहीं बताती, तब तक उनके खिलाफ कोई दमनात्मक कार्रवाई न की जाए। दूसरी ओर पंजाब सरकार की ओर से पेश विशेष अधिवक्ता ने कहा कि याचिका केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों और आशंकाओं पर आधारित है। उन्होंने अदालत को बताया कि फिलहाल उनके पास यह जानकारी नहीं है कि वास्तव में किसी जिले में एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं। इसके लिए विभिन्न जिलों से जानकारी एकत्र करनी होगी।राज्य सरकार के रुख पर भी उठे सवाल सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रुख पर भी सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि यदि एक सांसद अदालत में यह कह रहा है कि उसे मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आशंका है, तो राज्य को कम से कम यह स्पष्ट करना चाहिए कि मामला दर्ज है या नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी पक्ष का यह कहना कि उन्हें जानकारी नहीं है, प्रथम दृष्टया असामान्य प्रतीत होता है।

हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल आशंका के आधार पर व्यापक सुरक्षा देना कानून के अनुसार संभव नहीं है। इसके बावजूद अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक बिना अदालत की अनुमति के कोई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

फाजिल्का में पांच साल तक शारीरिक शोषण करने के बाद शादी से मुकरा प्रेमी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू किया जांच

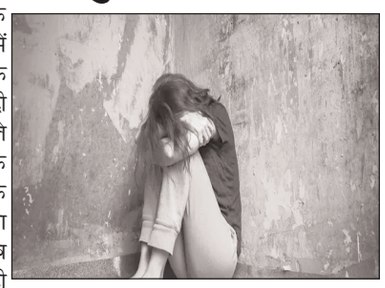

अबोहर। सदर थाना के अंतर्गत आते एक गांव में 22 वर्षीय युवती ने गांव के ही फौजी युवक पर शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने व पांच साल तक शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि अब आरोपित ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है व अन्य लड़की के साथ शादी कर रहा है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से उसकी शादी उक्त युवक से करवाने की मांग की है। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता ने बताया कि 32 वर्षीय फौजी युवक पांच साल पहले उसे घर से शादी का झांसा देकर भगा ले गया और चार साल उसे बठिंडा में किराये के कमरे में रखा, जहां उसे ग्यारहवीं और बारहवीं की पढाई करवाई। इस दौरान जब युवक ड्यूटी से छुट्टी पर आता तो उससे शारीरिक संबंध बनाता और उसके साथ ही रहता।पीड़िता के अनुसार पिछले एक साल से युवक ने उसे अबोहर में एक पीजी में रखा था और एक प्राइवेट कालेज में बीए में एडमिशन भी करवाई। दो दिन पहले उसे पता चला कि युवक का किसी अन्य लड़की के साथ विवाह किया जा रहा है। इस संबंधी जब पंचायत के पास गई तो परिवार द्वारा उन्हें पैसे लेकर बात रफा-दफा करने का आफर दिया गया।

आप सांसद चब्बेवाल को अमित शाह बनकर आया फोन, कहा- दिल्ली आकर मिलो; रवनीत बिट्टू ने बताया पॉलीटिकल ड्रामा

चंडीगढ़। होशियारपुर से आम आदमी पार्टी के सांसद डॉ. राजकुमार चब्बेवाल को एक संदिग्ध फोन कॉल आने के बाद पंजाब की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। सांसद ने आरोप लगाया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नाम पर उन्हें फोन कर भ्रमित करने की कोशिश की। मामले को लेकर सांसद ने पुलिस में शिकायत देने की बात कही है। डॉ. चब्बेवाल ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब दस बजे उन्हें एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने पहले उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और फिर दिल्ली आकर मिलने के लिए कहा। सांसद के अनुसार कॉल करने वाले की आवाज काफी हद तक अमित शाह जैसी लग रही थी, जिससे वह खुद भी कुछ समय के लिए हैरान रह गए। सांसद ने कहा कि शुरूआत में उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर केंद्रीय गृहमंत्री की ओर से इस तरह फोन क्यों किया जाएगा। बाद में उन्हें मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत देने का फैसला किया। पुलिस को दी पूरी जानकारी डॉ. चब्बेवाल ने कहा कि वह पुलिस को फोन नंबर और पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कॉल किसने और किस उद्देश्य से की। उन्होंने कहा कि यह किसी का मजाक भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई और मंशा है या नहीं, यह जांच का विषय है। यह मामला इसलिए भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है क्योंकि हाल ही में पंजाब से आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में लगातार यह चर्चा चल रही है कि भाजपा अन्य नेताओं और सांसदों से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है।बिट्टू का आरोप- झूठी कहानियों का लिया जा रहा सहारा रेल राज्य मंत्री एवं भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमित शाह जी का डर है या पॉलिटिकल ड्रामा? अब आप वाले झूठी कहानियों का सहारा ले रहे हैं। आप की लीडरशिप अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम का इस्तेमाल करके झूठी शिकायतें दर्ज करवाना सिर्फ.सस्ती शोहरत पाने का एक घटिया तरीका है। सच तो यह है कि अब आपके झूठ बिकना बंद हो गए हैं, इसीलिए ऐसे ड्रामे रचे जा रहे हैं। जनता सब जानती है। कांग्रेस छोड़ थामा था आप का हाथ गौरतलब है कि डॉ. राजकुमार चब्बेवाल मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी नेताओं में माने जाते हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने होशियारपुर सीट से जीत दर्ज की थी। इससे पहले वे चब्बेवाल से कांग्रेस के विधायक थे और वहां से इस्तीफा देकर आप जॉइन की। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हुए उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को बड़े अंतर से हराया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच की तैयारी में जुटी है। सांसद का कहना है कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह केवल मजाक था या इसके पीछे कोई राजनीतिक या अन्य उद्देश्य छिपा हुआ था।

पंजाब में फर्जी बिलिंग का बड़ा खेल बेनकाब, 15 करोड़ से ज्यादा कर घोटाले में लुधियाना का कारोबारी गिरफ्तार

चंडीगढ़। पंजाब सरकार के आबकारी एवं कर विभाग ने फर्जी बिलिंग और कर चोरी के एक बड़े नेटवर्क का पदार्फाश करते हुए लुधियाना की एक फर्म के निदेशक को गिरफ्तार किया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह बड़ी सफलता हासिल की गई है। कार्रवाई के विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा आज कर विभाग ने एक बेहद संगठित फर्जी बिलिंग नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त करते हुए मैसर्स एपीआई प्लास्टिक रिसाइक्लर्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना के डायरेक्टर एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता परमजीत सिंह को 85.4 करोड़ रुपये के फर्जी लेन-देन पर गलत तरीके से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने और

15.56 करोड़ रुपये का बड़ा जीएसटी घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। योजनाबद्ध तरीके से हुई टैक्स चोरी वित्त मंत्री ने कहा कि आरोपी फर्म योजनाबद्ध और संगठित टैक्स चोरी में शामिल थी। उन्होंने बिना वास्तविक रूप से माल प्राप्त किए, कई राज्यों में गैर-मौजूद और धोखाधड़ी वाली फर्मों द्वारा जारी किए गए फर्जी चालानों (बिलों) के आधार पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया। खुफिया टीमों ने यह भी पाया कि लेन-देन में शामिल कई सप्लायर फर्मों को संबंधित जीएसटी अधिकारियों द्वारा पहले ही स्वतः रद्द, निलंबित या गैर-कार्यशील घोषित किया जा चुका था। अब तक सामने आई कुल धोखाधड़ी 15.56 करोड़ रुपये की है और यह आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है क्योंकि हमारी जांच अभी भी सख्ती से जारी है। मंत्री ने विभाग द्वारा ई-वे बिलों और फास्टैग टोल डेटा के किए गए विस्तृत विश्लेषण की सराहना की। इस विश्लेषण ने निर्णायक रूप से यह साबित कर दिया कि ट्रांसपोर्ट दस्तावेजों में दर्शाए गए वाहन माल की घोषित आवाजाही से बिल्कुल मेल न खाने वाले स्थानों पर पाए गए थे, जो यह साबित करता है कि वास्तव में कोई ढुलाई नहीं हुई थी।जांच में ऐसे 407 अत्यधिक संदिग्ध वाहन आवागमन का खुलासा हुआ है, जिनमें 2.65 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जी आईटीसी शामिल है। आबकारी एवं कर मंत्री चीमा ने दस्तावेजों की जालसाजी की गंभीरता को उजागर करते हुए कहा कि जांच में धोखाधड़ी वाले डेबिट नोटों को शामिल करने के एक नए तरीके का भी खुलासा हुआ है, जिसके जरिए लगभग 5.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फर्जी आईटीसी तैयार किया गया था। मंत्री ने बताया कि डेबिट नोटों में बड़ी अनियमितताएं थीं, जिनमें टैक्स योग्य मूल्य और टैक्स की राशि को बराबर दर्शार्या गया था। जीएसटी कानून के तहत यह

आप सांसद चब्बेवाल को अमित शाह बनकर आया फोन, कहा- दिल्ली आकर मिलो; रवनीत बिट्टू ने बताया पॉलीटिकल ड्रामा

चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हालिया कार्रवाई में नाम सामने आने के बाद पंजाब सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं और यदि किसी भी जांच में वह दोषी पाए जाते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमन अरोड़ा ने कहा कि छापेमारी और पैसों से भरे बैगों की खबरें सामने आने के बाद वह खुद भी हैरान थे। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य उस समय हुआ जब शाम को प्रवर्तन निदेशालय की दूसरी विज्ञप्ति में उनका नाम शामिल कर दिया गया।अमन अरोड़ा ने आरोप

लगाया कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि पहली विज्ञप्ति में उनका नाम कहीं नहीं था, लेकिन बाद में जारी दूसरी विज्ञप्ति में अचानक उनका और गौरव धीर का नाम जोड़ दिया गया।22 सालों से है गौरव से पहचान उन्होंने कहा कि मामले में जिन अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें से कई नाम उन्होंने पहली बार सुने हैं। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि गौरव धीर उनके पुराने मित्र हैं। अमन अरोड़ा ने कहा कि उनकी और गौरव धीर की दोस्ती आज की नहीं बल्कि पिछले 22 वर्षों से है। उन्होंने कहा कि केवल दोस्ती के आधार पर किसी को गलत साबित नहीं किया जा सकता। अमन अरोड़ा ने कहा कि यह समझ से बाहर है कि यदि कोई व्यक्ति उनका मित्र है तो उसे लेकर उनका नाम विवाद में क्यों जोड़ा जा रहा है। अमन अरोड़ा ने कहा कि दोपहर तक पूरे मामले को लेकर अलग चर्चा चल रही थी, लेकिन शाम होते-होते अचानक उनका नाम सामने लाकर उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी गई। उन्होंने दावा किया कि यह सब एक साजिश के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां भी जांच एजेंसियां बुलाएंगी, वह पूरी तरह सहयोग करेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी भी जांच में उनके खिलाफ कुछ गलत साबित होता है तो वह राजनीति छोड़ने के लिए भी तैयार हैं।

राजनीतिक हलकों में अमन अरोड़ा के इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष लगातार ईडी कार्रवाई को लेकर सरकार और उससे जुड़े नेताओं पर सवाल उठा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है और आने वाले दिनों में इस प्रकरण में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

कपूरथला में नशा तस्कर के कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, पंचायत जमीन पर बना अवैध मकान गिराया

कपूरथला। पंजाब सरकार द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ह्नशों के खिलाफ जंगह्व अभियान के तहत शुक्रवार को कपूरथला जिले के गांव तोती में बड़ी कार्रवाई की गई। सिविल और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने पंचायत भूमि पर बने एक कथित अवैध निर्माण को मशीन चलाकर गिरा दिया। यह कार्रवाई गांव के रहने वाले परविंदर सिंह उर्फ पिंदा के खिलाफ की गई, जो फिलहाल जेल में बंद है। मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव तूरा ने बताया कि आरोपी द्वारा पंचायत की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया गया था। प्रशासन की ओर से पहले कई बार नोटिस जारी कर कब्जा हटाने को कहा गया, लेकिन कब्जा खाली नहीं किया गया। इसके बाद प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई विकास खंड एवं पंचायत अधिकारी सुल्तानपुर लोधी गुरमीत सिंह के आदेशों के बाद की गई। प्रशासन का कहना है कि आरोपी परविंदर सिंह उर्फ पिंदा असामाजिक गतिविधियों और नशा तस्करी से जुड़े मामलों में शामिल रहा है। कपूरथला जेल में बंद है आरोपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों में मादक पदार्थ कानून के तहत सात मामले दर्ज हैं। फिलहाल वह कपूरथला की आधुनिक जेल में बंद है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ सरकार की नीति पूरी तरह सख्त है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। मशीन की मदद से अवैध निर्माण को गिराकर पंचायत भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पंजाब सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि नशा तस्करी में शामिल लोगों और उनके अवैध नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की जाए। इसी के तहत जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है।प्रशासन जारी रखेगा ऐसी कार्रवाई स्थानीय लोगों का कहना है कि गांवों में नशे के खिलाफ हो रही ऐसी कार्रवाई से प्रशासन का सख्त संदेश जा रहा है। लोगों ने उम्मीद जताई कि इससे युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने में मदद मिलेगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव तूरा ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता नशा कारोबार में पाई गई तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वे नशा तस्करी से जुड़ी जानकारी पुलिस को दें ताकि ऐसे नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

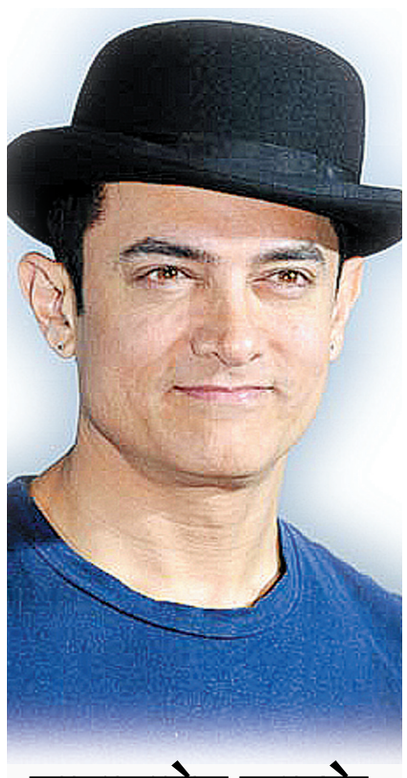

दादासाहेब फाल्के की बायोपिक क्यों रुकी? आमिर ने बताई वजह

करीब एक साल पहले आमिर खान और राजकुमार हिरानी ने भारतीय सिनेमा के जनक दादासाहेब फाल्के पर बायोपिक बनाने का एलान किया था। इस घोषणा के बाद फिल्म को लेकर काफी उत्साह था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

'स्क्रिप्ट से खुश नहीं, इसलिए फिलहाल रोक दी फिल्म'

अमर उजाला से बातचीत में आमिर खान बताते हैं, 'दादासाहेब फाल्के की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, जिस पर राजू काम कर रहे थे। उन्होंने इसके तीन ड्राफ्ट बनाए, लेकिन अभी तक वो स्क्रिप्ट से पूरी तरह खुश नहीं हैं। इसलिए उन्होंने इस फिल्म को फिलहाल बैक बर्नर पर रख दिया है। हो सकता है कि आगे चलकर वो इस पर दोबारा काम करें। फिलहाल इस वक्त राजू '3 इडियट्स 2' पर काम कर रहे हैं। मैंने उसकी कहानी सुनी है, बहुत अच्छी बनी है और अभी उस पर आगे काम चल रहा है।'

'10 साल बाद लौटेंगे '3 इडियट्स' के किरदार'

वह बताते हैं, 'ये बहुत ही अनोखी कहानी है। इसमें '3 इडियट्स' के किरदारों की कहानी दिखाई जाएगी, लेकिन करीब दस साल बाद की। यह एक बहुत खूबसूरत कहानी है, जिसे अभिजात और राजू ने बहुत अच्छे से लिखा और सोचा है।' आमिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'तो एक बार फिर मुझे फुनसुख वांगडू के उस किरदार में उतरना पड़ेगा।'

'सितंबर या अक्टूबर से शुरू हो सकती है मेरी अगली फिल्म'

अपने आगे के प्लान को लेकर आमिर कहते हैं, 'मैं पिछले आठ महीनों से कई स्क्रिप्ट्स सुन रहा हूं। 'एक दिन' के रिलीज होने के बाद मैं अपने करियर पर थोड़ा फोकस करूंगा। कई कहानियां हैं जो मुझे पसंद आई हैं।' वह आगे कहते हैं, 'अभी मैंने तय नहीं किया है कि कौन सी फिल्म करूंगा, लेकिन अगले एक-दो हफ्तों में, ज्यादा से ज्यादा एक महीने में फैसला ले लूंगा। मेरा अनुमान है कि इस साल के सितंबर या अक्टूबर से शूटिंग शुरू हो जाएगी।'

पवन सिंह से ब्रेकअप के बाद फिर इश्क में पड़ीं अक्षरा सिंह

अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने हाल ही में अपनी लव लाइफ पर बात की है। एक वक्त में उनके प्यार के चर्चे भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के साथ थे। दोनों का अफेयर रहा, मगर बाद में इनके बीच दूरियां आ गईं और ब्रेकअप हो गया। इतना ही नहीं, यह रिश्ता एक बुरे मोड़ पर टूटा था। अक्षरा ने पवन सिंह पर कई आरोप भी लगाए। हालांकि, पवन सिंह से ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस अब आगे बढ़ गई हैं। उनकी जिंदगी में फिर से प्यार ने दस्तक दी है।

अक्षरा बोलीं- 'भूतकाल पर थोड़ी अटकी रहूंगी'

अक्षरा सिंह ने हाल ही में यूट्यूब चैनल जिंदाबाद को दिए इंटरव्यू में अपने करियर और जिंदगी को लेकर कई दिलचस्प बातें साझा कीं। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि क्या उन्हें दोबारा प्यार नहीं हुआ? इस पर अक्षरा ने मुस्कुराते हुए कहा, 'हुआ है ना। चल रहा है। दोबारा क्या होता है, जो पुराना हो गया वो तो भूतकाल में चला गया। अभी मैं भविष्य की चिंता करूंगी, वर्तमान की चिंता करूंगी या भूतकाल पर अटकी रहूंगी'।

किसे डेट कर रही हैं अक्षरा सिंह?

बातचीत के दौरान अक्षरा ने बताया कि वे एक अनजान शख्स को डेट कर रही हैं। उन्होंने उस शख्स की पहचान उजागर नहीं की। उन्होंने कहा कि वे किसी की नजर नहीं चाहतीं। अक्षरा ने कहा, 'हां मैं प्यार में हूं, लेकिन अभी टाइम है। फिलहाल मैं प्यार के प पर पहुंची हूं। थोड़ा प्रोसेस होने दीजिए, फिर मैं सब बताऊंगी'। अक्षरा सिंह ने आगे कहा कि बिना प्यार के कोई नहीं रह सकता।

मुझे नजर बहुत जल्दी लगती है

प्यार का नाम पूछे जाने पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे नजर बहुत जल्दी लगती है। अगर मैंने नाम बता दिया और नजर लग गई तो? शादी का अभी नहीं पता, लेकिन पहले जिनसे प्यार हुआ है उन्हें जान लें। बहुत सी चीजें हैं, वो जब समझ आ जाएंगी तब देखा जाएगा शादी का'। अक्षरा ने कहा कि अभी शुरुआती दौर है, वे खुद अभी फिगर आउट कर रही हैं। बता दें कि एक टाइम पर अक्षरा और पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चित कपल थे। मगर, साल 2018 में पवन सिंह ने कथित तौर पर अक्षरा को धोखा देकर ज्योति सिंह से शादी कर ली। अक्षरा ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए थे। फिलहाल पत्नी ज्योति सिंह के साथ भी पवन सिंह का विवाद कोर्ट में चल रहा है।

इसी साल शुरू होगी रणवीर स्टारर 'प्रलय' की शूटिंग

अभिनेता रणवीर सिंह 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की जबरदस्त सफलता के बाद अब दर्शकों को अपकमिंग फिल्म 'प्रलय' के रूप में एंटरटेनमेंट का नया डोज देने को तैयार हैं। 'प्रलय' की शूटिंग इस साल अगस्त से शुरू होने वाली है। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि रणवीर सिंह और निर्देशक जय मेहता के बीच क्रिएटिव मतभेदों के कारण फिल्म में रुकावट आ गई है, लेकिन फिल्म से जुड़े सूत्रों ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। जानकारी के अनुसार, 'प्रलय' को लेकर फैलाई जा रही अनिश्चितता वाली खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। सूत्र के अनुसार, फिल्म का प्री-प्रोडक्शन काम पहले ही शुरू हो चुका है और रणवीर सिंह व निर्देशक जय मेहता स्क्रिप्ट को अंतिम रूप देने में लगातार चर्चा कर रहे हैं।

'वाराणसी' की वजह से इस साल मेट गाला में नहीं शामिल होंगी प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग में बिजी हैं। इस वजह से उन्होंने कई प्रोग्रामों में जाना रद्द कर दिया है। खबरें हैं कि काम के चलते वह इस साल मेट गाला में नहीं शामिल होंगी। यह बात इसलिए ज्यादा ध्यान खींच रही है क्योंकि रेड कार्पेट से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मेट गाला में प्रियंका दुनिया भर से आने वाले सबसे जाने-पहचाने चेहरों में से एक रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा मेट गाला 2026 में शामिल नहीं होंगी। यह इवेंट 4 मई को न्यूयॉर्क के मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में होने वाला है। ब्रिटिश वोग के मुताबिक जब मेट गाला का प्रोग्राम चल रहा होगा तब वह शायद अंटार्कटिका में 'वाराणसी' की शूटिंग कर रही होंगी। मई के पहले सोमवार को अभिनेत्री बिजी हो सकती हैं।

खलेगी प्रियंका की गैरमौजूदगी

पिछले कुछ वर्षों में प्रियंका चोपड़ा ने मेट गाला में कई यादगार अपीयरेंस दिए हैं। अपने शानदार ट्रेंच कोट गाउन से लेकर बोल्ड काउचर लुक्स तक, वह लगातार रेड कार्पेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सेलिब्रिटीज में से एक रही हैं। उनके अपीयरेंस अक्सर ग्लोबल पॉप कल्चर की बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं। इस वजह से इस साल उनकी गैर-मौजूदगी महसूस की जाएगी।

'वाराणसी' के बारे में

आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आने वाली हैं। वह इसकी शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन होंगे। यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को रिलीज हो सकती है।

जल्द ही खाकी वर्दी में अपना 'कर्तव्य' निभाते नजर आएंगे सैफ अली खान

सैफ अली खान जल्द ही खाकी वर्दी में अपना 'कर्तव्य' निभाते नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स की उनकी आगामी फिल्म 'कर्तव्य' की रिलीज डेट आज सामने आ गई है। टीजर के जारी होने के बाद से ही फैंस फिल्म का इंतजार कर रहे थे, अब आज मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट घोषित कर दी है।

शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तले बनी पुलिस-ड्रामा फिल्म 'कर्तव्य' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने आज एक पोस्ट के जरिए फिल्म की रिलीज डेट घोषित की है। जिसके तहत 'कर्तव्य' 15 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करेगी। नेटफ्लिक्स ने फिल्म से सैफ अली खान का एक पोस्टर साझा किया। इसमें सैफ पुलिस की वर्दी में निराश नजर आ रहे हैं। उनके सामने आग जलती दिख रही है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा गया, 'कर्तव्य के इस चक्रव्यूह में हर फैसला एक इम्तिहान होगा।'

ऐसी है कहानी

'कर्तव्य' की कहानी एक पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो ऐसी दुनिया में अपना काम करने की कोशिश करता है जहां सही और गलत की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। जहां उसके सामने भावनात्मक और नैतिक दुविधाएं आती हैं, क्योंकि वह पेशेवर जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। जैसे-जैसे खतरे बढ़ते हैं, अधिकारी खुद को अपनी सीमाओं तक धकेला हुआ पाता है और न्याय की कीमत और चुप्पी के परिणामों पर सवाल उठाने लगता है।

फिल्म का निर्देशन 'भक्षक' फेम पुलकित ने किया है। फिल्म में सैफ अली खान मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा रसिका दुगल, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन और मनीष चौधरी सरीखे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहक किया गया है। इसे प्रोड्यूस गौरी खान ने किया है। 'सेक्रेड गेम्स' की सफलता के बाद सैफ अली खान एक बार फिर पुलिस वाले किरदार में नजर आएंगे।

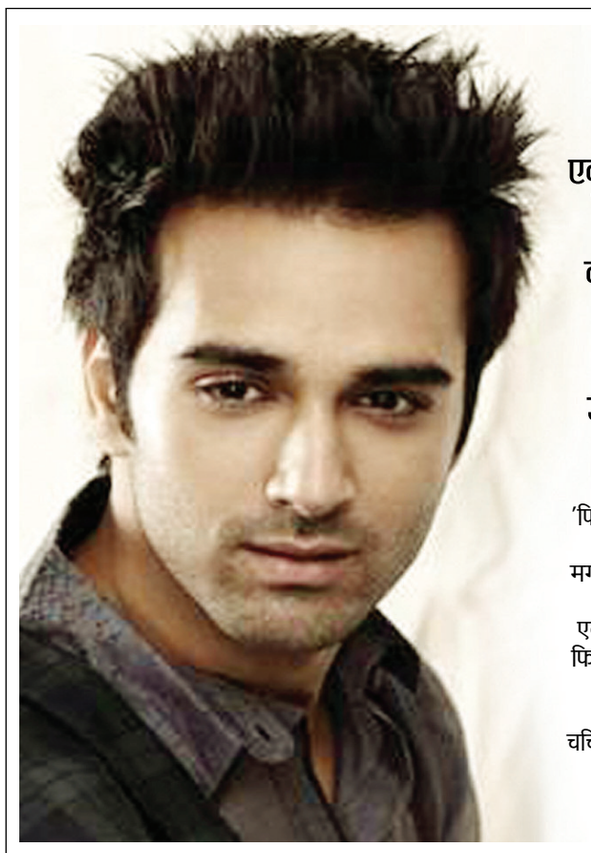

हमारा स्ट्रगल फिल्म हिट होने के बाद भी खत्म नहीं होता

एक्टर पुलकित सम्राट इस वक्त नई सीरीज 'ग्लोरी' को लेकर सुर्खियों में हैं। 'फुकरे' जैसी हिट फ्रैंचाइजी का हिस्सा रहे पुलकित ने कहा कि हिट देने के बाद भी स्ट्रगल खत्म नहीं होता और इसलिए उन्हें काम मांगने में कोई शर्म नहीं आती। उन्होंने स्ट्रगल के अलावा 'ग्लोरी' में रोल और उन खामियों पर बात की, जो दूर की हैं।

'फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल के दौरान आपको लगता है कि सबसे मुश्किल काम पहला ब्रेक मिलना है, मगर मेरा यकीन मानिए उससे भी ज्यादा मुश्किल है लगातार काम मिलते रहना।' यह कहना है एक्टर पुलकित सम्राट का। फिल्म 'बिट्टू बॉस' से फिल्मी करियर शुरू करने वाले पुलकित ने अपने इस सफर में सुपरहिट 'फुकरे' फ्रेंचाइजी से लेकर 'डॉली की डोली' और 'पागलपंती' जैसी चर्चित फिल्मों से अपनी पहचान बनाई, मगर पुलकित का कहना है कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए लगातार मेहनत करने रहनी पड़ती है।

पुलकित की नई वेब सीरीज 'ग्लोरी' सपनों और महत्वाकांक्षाओं पर आधारित है। ऐसे में, एक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए की गई जद्दोजहद को याद करते हुए पुलकित बताते हैं, 'इंडस्ट्री में हमारा कोई गॉडफादर नहीं था। हम आउटसाइडर थे और यहां अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन जगह आप तभी बना पाएंगे, जब आपको कुछ काम मिलेगा। इसलिए, पहले तो वो काम मिलना जरूरी है। उस पर आपको लगता है कि सबसे मुश्किल चीज यह पहला काम मिलना ही है। आप सोचते हैं कि बस एक ब्रेक मिल जाए, लेकिन मेरा यकीन करिए कि आपको लगातार काम मिलते रहना सबसे मुश्किल चीज है और उसके लिए आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। आपको जाकर लोगों को खुद को बतौर प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। वह बहुत जरूरी है।'

काम मांगने में कोई शर्म नहीं है

'खुशकिस्मती से आज हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म हैं कि कोई कलाकार ये बोले कि मुझे काम नहीं मिल रहा तो मेरे हिसाब से वो काम करना ही नहीं चाहता क्योंकि आज काम करने की बहुत सारी जगहें हैं। मैंने जब शुरुआत की थी, तब ऐसा नहीं था। आज बहुत सारे मंच हैं। बस आप घर से निकलिए, लोगों से बोलिए कि मुझे काम करना है। काम मांगिए और काम मांगने में कोई शर्म नहीं है, जो पहले मुझे लगता था कि मैं दिखा तो दिया। 'फुकरे' कर ली, फिल्म सुपरहिट हो गई, अब तो कल से लाइन लग जाएगी लेकिन कोई लाइन नहीं लगती। यह सच्चाई है। आपके लिए दरवाजे बेशक खुल जाते हैं पर उस दहलीज को पार करके अंदर जाना आपका काम है और मुझे लगता है कि सेट से ज्यादा काम सेट के बाहर रहता है।'

मैं जैसा पहले था, उस पर गर्व नहीं

सीरीज में पुलकित अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करते हैं। असल जिंदगी में उन्होंने अपनी किसी खामी पर जीत पाई है? यह पर उन्होंने बताया, 'मुझमें बहुत खामियां थीं। एक वक्त पर मैं अपने आप का एक ऐसा वर्जन था जिस पर मुझे आज बिल्कुल गर्व नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो मुझे धीरे-धीरे समझ में आई। जब मैं घर से निकला, अकेले उड़ान भरनी शुरू की, ठोकरें खाई तब मुझे समझ आई कि जीने का ये सही तरीका नहीं है। शुरू में हमें ज्यादा समझ नहीं होती है। आप कभी मजाक में किसी को ऐसी बात बोल देते हैं जो शायद उसे बुरी लगे। आज समझ में आता है कि नहीं यार, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था या मुझे सेट पर ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था या मैं इस सिचुएशन को बिना गुस्से के भी हैंडल कर सकता था। तब जब लोग आपको बोलते भी हैं न तो भी समझ में नहीं आता है, जब तक आपके पिछवाड़े पर लात नहीं पड़ती।'

बॉक्सिंग ने सिखाया जिंदगी का सबक

सीरीज में बॉक्सर की भूमिका के लिए की तैयारी पर वह बताते हैं, 'इसमें मेरा किरदार एक प्रोफेशनल बॉक्सर का है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ी। बॉक्सिंग को समझना पड़ा और जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की, तब मुझे समझ आया कि बॉक्सिंग केवल फिजिकल नहीं है, यह एक माइंड गेम भी है। यह एक शतरंज के खेल की तरह है जहां आप रिंग में अपने विरोधी का दिमाग पढ़ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं और मैं कहूंगा कि बॉक्सिंग ने मुझे ये सिखाया कि उन्हीं नियमों को अपनी असल जिंदगी में भी कैसे उतार सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में उससे कैसे निकल सकते हैं। बॉक्सिंग ने मुझे यह सिखाया कि सिर्फ फिजिकली फिट दिखना काफी नहीं है।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अनुज कुमार के द्वारा एजीएस पब्लिकेशंस एफ 23, सेक्टर 6, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 से मुद्रित व गांव बुखारीपुर, पोस्ट ढवारसी, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश पिन कोड 244242 से प्रकाशित।
संपादक-अनुज कुमार, R.N.I. No.-UPHIN/2023/86483, मो0.945688 4327, E-mail-officialsabkasapna@gmail.com, www.sabkasapna.com नोट- समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र अमरोहा जनपद न्यायालय होगा।